प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक

संस्थापक स्व. श्री ठाकुरदासजी खुजनेरी

मालव समाचार

इंदौर | ■ वर्ष : 61 ■ अंक 10 ■ 30 मार्च 2025 ■ पृष्ठ-12 ■ मूल्य - 3.00 प्रकाशन के 6 दशक

मोदी का पाकिस्तान को करारा जवाब

आतंकवाद फैलाने का लगाया आरोप

लेक्स फ्रीडमै के साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा...

संघ से मुझे जीवन के संस्कार मिले

मार्च की 16 तारीख की शाम को पीएम नरेंद्र मोदी और लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट जारी हुआ। 3 घंटा 17 मिनट के इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने वैश्विक राजनीति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, भारत की विकास यात्रा और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब दिए हैं। एक ओर पीएम मोदी के इस इंटरव्यू को जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वहीं, दूसरी तरफ इंटरव्यू में चीन को लेकर पीएम मोदी की 'सकारात्मक टिप्पणियों' की शी जिनपिंग सरकार ने भी सराहना की है।

अमेरिकी पॉडकास्टर के इंटरव्यू में ट्रंप और चीन पर पीएम मोदी के 5 छिपे संदेश

विशेष रिपोर्ट

पेज-6-7-8

धान घोटाला, सिंहस्थ के लिए जमीन अधिग्रहण मुद्दा उठा, पंचायत विभाग को लेकर सबसे ज्यादा सवाल

अपने ही विधायकों के सवालों से घिरी सरकार... असहज हुए मंत्री

पेज- 2

नगरीय निकायों से लेकर पंचायतों तक में

करोड़ों का घोटाला

आपदा का मुआवजा अफसरों ने रिश्तेदारों के खातों में डाला, सीएजी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

पेज- 3

मत खोल मेरी किस्मत की किताब को,
हर उस शख्स ने दिल दुखवाया जिस पे नाज था।।

विपक्षी गठबंधन के रास्ते की बाधा कौन?

चुनाव के सबक की अनदेखी की तो कांग्रेस और सभी प्रादेशिक पार्टियों की मुश्किलें और बढ़ेंगी

पेज- 05

गुजरात होगा नया कुरुक्षेत्र!

» राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमियों को स्वीकारा और सुधार का वादा किया

पेज- 09

NDA गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया!

बिहार में बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी भाजपा

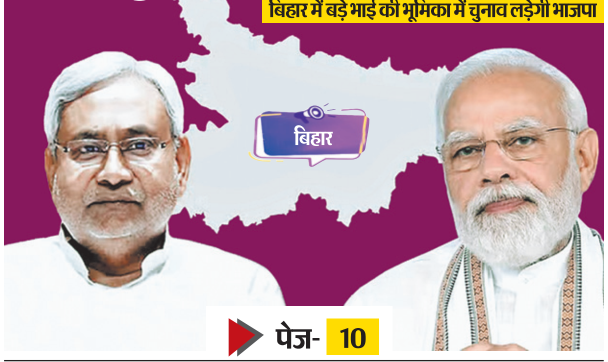

पेज- 10

झारखंड में राजनीतिक भूचाल के संकेत

सीता सोरेन की घर वापसी की तैयारी!

दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज

बीजेपी की नजर ट्रिपल इंजन सरकार पर, सियासी स्थिति भी पक्ष में

पेज- 11

अपने ही विधायकों के सवालों से घिरी सरकार... असहज हुए मंत्री

धान घोटाला, सिंहस्थ के लिए जमीन अधिग्रहण मुद्दा उठा, पंचायत विभाग को लेकर सबसे ज्यादा सवाल

भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा का 10 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र हंगामेदार रहा है। विपक्ष ने परिवहन घोटाला, बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।योजनाओं में लेटलतीफी, धान उपार्जन घोटाले और सिंहस्थ के लिए अधिगृहीत की जाने वाली किसानों की जमीन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल पूछे। इनका जवाब देने में विभागीय मंत्री असहज हो गए।

सबसे ज्यादा सवाल पंचायत, राजस्व और नगरीय विकास विभाग से जुड़े

विधायकों ने सबसे ज्यादा 245 सवाल पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को लेकर पूछे। इस विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। विधायकों ने जनपद पंचायतों के खातों से पैसे निकाले जाने, भ्रष्टाचार के मामलों में उच्च स्तरीय जांच, सड़क निर्माण में अनियमितताएं, पेसा एक्ट, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े सवाल पूछे।वहीं, राजस्व विभाग को लेकर 215 सवाल पूछे गए। जिनमें जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें, अतिक्रमण, राहत राशि का भुगतान, किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना से जुड़े सवाल शामिल थे। नगरीय आवास एवं विकास विभाग को लेकर 183 सवाल पूछे गए। इनमें पीएम आवास योजना, अवैध कॉलोनियों और प्राधिकरणों से संबंधित सवाल शामिल थे।

सिंहस्थ के लिए तंबू की जगह पक्के मकान क्यों?

उज्जैन में अप्रैल-मई 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए किसानों की जमीन के स्थायी अधिग्रहण पर आलोट के बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा। बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान मालवीय ने कहा कि उज्जैन का किसान डरा हुआ है। उसकी जमीन छीनी जा रही है।इस पर तराना के कांग्रेस विधायक महेश परमार ने मालवीय का समर्थन किया। मगर, उज्जैन उत्तर से बीजेपी विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने आपत्ति दर्ज की। मालवीय के इस मुद्दे से सरकार असहज नजर आई। मालवीय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2 हजार करोड़ रुपए उज्जैन सिंहस्थ के लिए रखे हैं। उज्जैन उन पर अभिमान करता है। उज्जैन उनको अपना नेता मानता है लेकिन, आज उज्जैन का किसान बहुत डरा और परेशान है। क्योंकि, सिंहस्थ के नाम पर उसकी जमीन पहले केवल 3-6 महीनों के लिए अधिगृहीत की जाती थी लेकिन आज उन्हें स्थायी अधिग्रहण का नोटिस दिया गया है। पता नहीं, किस अधिकारी ने यह विचार रखा है कि स्पिरिचुअल सिटी (आध्यात्मिक नगरी) बनाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी किसी सिटी में नहीं रहती है। वह तो त्याग करने वाले लोगों से होती है। हम क्रांक्रीट के भवन बनाकर स्पिरिचुअल सिटी नहीं बना सकते।इसके पीछे उज्जैन के किसानों को आशंका है कि कॉलोनाइजर्स और भू-माफिया का यह षड्यंत्र है। पैसा प्रतिभा से कमाया जाता है और जो जितना प्रतिभाशाली होता है, उतना ही धनवान भी होता है, ऐसा माना भी जाता है।

सिंहस्थ की जमीन का ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते

चिंतामणि मालवीय ने कहा- हम तो पानी के बुलबुले हैं, भोर के सितारे हैं, लेकिन सिंहस्थ पांच हजार वर्षों तक चलेगा। जब तक इस देश में हिंदू है और विश्व में कहीं भी हिंदू हैं, सिंहस्थ चलेगा। हम सिंहस्थ की जमीन का इस तरह प्रयोग नहीं कर सकते कि उससे बड़ा नुकसान हो जाए।मालवीय ने कहा- मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आता है कि 'ये जब्र भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई'। कहीं यह न हो कि हम सिंहस्थ की जमीन को हमेशा-हमेशा के लिए खो दें। यह उन अधिकारियों के लिए भी है, जो इस तरह की सलाह देते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है, जिन्होंने जमीन नहीं देखी है। सिंहस्थ तंबुओं में होता है, वह बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे हैं। कॉलोनाइजर्स को लाभ देना चाहते हैं।

अब करना पड़ रहा नोटिस का सामना

भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय को भाजपा ने शो-कॉज नोटिस जारी किया है। मालवीय ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीनों के स्थायी अधिग्रहण को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा था। मामले की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची, इसके बाद प्रदेश नेतृत्व की ओर से मालवीय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।पार्टी के नोटिस पर मालवीय ने कहा-विधायक के नाते बात रखी ।नोटिस मिलने के बाद वे तथ्यों के साथ पार्टी को जवाब देंगे। बीजेपी विधायक बोले- माफी मांगना मेरा स्वभाव नहीं है।

अजय विश्नोई ने पूछा....

धान उपार्जन घोटाले की जांच में देरी क्यों?

जबलपुर की पाटन सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने धान उपार्जन घोटाले पर अपनी ही सरकार और सिस्टम को घेरा। जबलपुर में धान खरीदी में 5 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है, ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रही है।विश्नोई ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार से पूछा कि घोटाले को अंजाम देने के लिए फर्जी आरओ (रिलीज ऑर्डर) जारी किए गए। जिन ट्रकों से धान का परिवहन हुआ वो टोल नाकों से गुजरकर ग्वालियर, उज्जैन, मुरैना जैसे शहरों में गए। इसकी जांच आसानी से हो सकती है। एक माह से ज्यादा समय होने के बावजूद अब तक जांच पूरी नहीं हुई है। जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है ?खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा- किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जहां भी कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की गड़बड़ियां सामने आएंगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सिरोंज विधायक ने पूछा

किसान सम्मान निधि की किस्त कब मिलेगी?

सिरोंज के विधायक उमाकांत शर्मा ने सरकार को घेरते हुए पूछा- मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त किसानों को कब मिलेगी ? विदिशा जिले के कितने किसानों को दोनों योजनाओं का फायदा नहीं मिलने की शिकायतें की गई हैं ? उनका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है ?इस पर सरकार ने जवाब दिया- योजनाओं का फायदा नहीं मिलने की 19,481 शिकायतें सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर मिली थी। इनमें से सिर्फ 776 शिकायतों का निराकरण होना शेष है। 663 शिकायतें फरवरी माह में दर्ज हुई हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है।शर्मा ने ग्राम पंचायतों की जांच, अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता, नगर निगमों की सड़कों की जांच और वनों की अवैध कटाई को लेकर भी सरकार को घेरा।

भिंड विधायक बोले

मंत्री जी, आप भ्रष्ट अफसर को बचा रहे हैं

भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये तक कहा कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, भ्रष्ट अफसर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, कुशवाहा ने कहा कि भिंड में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक प्रदीप जैन की लापरवाही से बिजली कटौती हो रही है।इस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पर्याप्त बिजली दी जा रही है। तोमर के इस जवाब पर कुशवाह बोले कि मंत्री जी आप भ्रष्ट अधिकारी को बचा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कर जांच कराई जानी चाहिए। वहीं, कुशवाहा का साथ देते हुए बीजेपी विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान ने कहा- बिजली विभाग के अफसर हमेशा गांवों में ब्लैकआउट की स्थिति रखते हैं। सवाल पूछने पर गलत जानकारी देते हैं।नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कहा कि सत्ता पक्ष का विधायक आवाज उठा रहा है, इसलिए इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष की बात तो सरकार सुनती नहीं है। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि विधायक की भावनाओं के आधार पर कार्रवाई होगी, किसी भी हालत में अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा।

सरकार बेटी पढ़ाओ की बात करती है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं

भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने उनके विधानसभा क्षेत्र के नयागांव में नया गर्ल्स कॉलेज खोलने के मुद्दे पर उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार को घेरा। कुशवाहा ने ये तक कहा कि सरकार बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है।दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 6 मार्च 2024 को भिंड में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वादा किया था कि नया गांव में नवीन महाविद्यालय खोला जाएगा। लेकिन एक साल बाद भी प्रक्रिया शुरू तक नहीं हुई।

सबनानी ने उठाया पीएम आवास में लेट-लतीफी का मुद्दा..

भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से भोपाल के कोटरा स्थित गंगानगर में प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन आवासों का छह साल में भी निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। बार-बार इसकी समय सीमा बढ़ती जा रही है। इसके चलते हितग्राही किराए से रहने को मजबूर हैं। उन्हें आवास के लिए राशि दी जानी चाहिए।इसके जवाब में मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा- ठेकेदार के स्तर पर काम नहीं किया गया है। बीच में कोविड के कारण भी देरी हुई। कई बार हितग्राही का समय से पैसा जमा नहीं हुआ, इस कारण से भी दिक्कत हुई है। मंत्री के जवाब के बाद विधायक सबनानी ने कहा कि भोपाल में इस तरह के कुल 14 प्रोजेक्ट हैं। उनके मामले में भी ध्यान देने की जरूरत है।

नगरीय निकायों से लेकर पंचायतों तक में करोड़ों का घोटाला

आपदा का मुआवजा अफसरों ने रिश्तेदारों के खातों में डाला, सीएजी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

भोपाल। प्रदेश में अफसरों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक को जहां भी मौका मिल रहा है, भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करने में पीछे नही रह रहे हैं। ऐसे मामलों में उन्हें जनप्रतिनिधियों का भी साथ मिलता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हाल ही में सदन में पेश की गई सीएजी के रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। यह खुलासा नगरीय निकायों और पंचायतों को लेकर किया गया है। इसमें बताया गया है कि निकाय और ग्राम पंचायतों में संपत्ति कर, शिक्षा और विकास उपकर आदि की वसूली में भी गंभीर लापरवाही और पब्लिक के साथ भ्रष्टाचार का खेल किया गया है। कर्मचारियों को अस्थायी अग्रिम के नाम पर बांटी गई 7 करोड़ रुपए की राशि वापस नहीं ली गई। वहीं, 35 निकायों में शहरी विकास उपकर की वसूली गई 20.43 करोड़ की राशि सरकारी खातों में जमा नहीं की गई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग के अनुदान के रूप में 1364 करोड़ रुपए की राशि वित्त विभाग ने हस्तांतरित नहीं की। चयनित जनपद पंचायतों में मजदूरी और सामग्री के लिए 30.24 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। 10 ग्राम पंचायतों में 1.51 करोड़ की लागत के 62 व्यक्तिगत कुएं (कपिल धारा कूप) फर्जी ढंग से मंजूर किए गए, जिसके कारण 62 में से 46 अधूरे रह गए। 15वें वित्त अनुदान से स्वीकृत कुल 19.16 करोड़ के काम, जिनका मूल्य 15 लाख से कम था, जिला पंचायत और जनपद पंचायत विकास योजना में शामिल नहीं किए गए। 4 जिला पंचायतों और 6 जनपद पंचायतों ने 3 करोड़ की 52 सीमेंट कांक्रीट सडकों को मंजूरी दी, वहीं 9 चयनित जिला पंचायतों ने 15.55 करोड़ के निर्माण के लिए मंजूरी की स्वीकृति नहीं दी। 64 ग्राम पंचायतों ने सामग्री मद में 5.07 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 2.72 लाख मानव दिवस का सृजन नहीं हुआ। इसके अलावा 66 स्टॉप डैम में से 10 स्टॉप डैमों में घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया।

स्थानीय निकायों में कहां क्या गड़बड़ी

- 46 नगरीय निकायों ने संपत्ति कर, शिक्षा और विकास उपकर की 427 करोड़ की राशि के बदले 178 करोड़ की वसूल किए जा सके। जल शुल्क, लाइसेंस शुल्क, भूमि और भवन किराया आदि का 303 करोड़ के बदले केवल 88 करोड़ की वसूली की गई।
- 12 नगरीय निकायों ने कर्मचारियों को अस्थायी अग्रिम के नाम पर 7 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उसकी वसूली नहीं की।
- 35 नगरीय निकायों में शहरी विकास उपकर के रूप में 51 करोड़ वसूले, लेकिन यह राशि सरकारी खाते में जमा नहीं की, वहीं 33 निकायों ने 94.84 करोड़ का शिक्षा उपकर वसूला और 69.79 करोड़ का उपयोग किया, लेकिन 25 करोड़ की राशि बैंकों में जमा पड़ी रही।
- राज्य सरकार ने कोविड महामारी के दौरान नगरीय निकायों को 85 करोड़ रुपए कम जारी किए। उधर, पानी की मांग के मुकाबले 9 नगरीय निकायों में भंडारण क्षमता थी।
- नगरीय निकायों में हर घर में पाइप से पानी की आपूर्ति में भी निकाय विफल रहे हैं। 2 लाख 54 हजार घरों की अपेक्षा एक लाख 67 हजार में ही अधिकृत जल कनेक्शन पाए गए।
- 13 नगरीय निकायों ने 4, 341 भवन निर्माण की अनुमति दी और संबंधित आवेदकों से छत जल संचयन के लिए एक करोड़ 35 लाख रुपए की सुरक्षा राशि जमा कराई गई, जबकि इन निकायों ने न तो आवेदकों द्वारा किए गए छत जल संचयन के काम का सत्यापन किया और न हीं आवेदकों की और से छत जल संचयन संरचनाएं बनाने का प्रयास किया गया।
- 14 नगरीय निकायों में ओएंडएम व्यय 207 करोड़ था, जिसके विरुद्ध निकायों ने प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष 480 से 2,400 रुपए के बीच विभिन्न दरों पर उपभोक्ताओं से 75.95 करोड़ की मांग की गई। 13 निकायों में वास्तविक लागत की तुलना में मांगे गए उपयोगकर्ता शुल्क में घाटा 30 से 93 प्रतिशत तक था। साथ ही 14 नगरीय निकायों ने जल शुल्क के कारण वसूली के लिए बकाया राशि 62.79 करोड़ थी।

13 जिलों में 23.81 करोड़ की गड़बड़ी

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की विधानसभा में पेश रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 13 जिलों में 23.81 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों व उनके रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 से 2022 के बीच मप्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को 10,060 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की गई लेकिन इसमें से 13 जिलों में 23.81 करोड़ रुपए की राशि फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई। सरकारी कर्मचारियों ने फर्जी स्वीकृति आदेश तैयार कराए। अपने तथा रिश्तेदारों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए। कैग ने सरकार से सिफारिश की है कि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से उन सभी जिलों में आपदा राहत राशि वितरण की जांच कराएं, जो कैग की जांच में शामिल नहीं हैं।

लेबर वेलफेयर बोर्ड में 5 साल में 120 करोड़ रुपए की गड़बड़ी

मप्र विधानसभा में श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मचारी कल्याण मंडल (वर्कर वेलफेयर बोर्ड) को लेकर कैग (नियंत्रक महालेखा रीक्षक) की रिपोर्ट में करीब 120 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के खुलासे हुए हैं। यह रिपोर्ट 2017-18 से 2021-22 के बीच के कामों को लेकर बनाई गई है। इसमें बताया गया है कि मप्र सरकार की प्रसूति सहायता योजना के लिए बोर्ड ने 2017-18 और 2019-20 के दौरान नेशनल हेल्थ मिशन को 80.47 करोड़ रुपए की राशि दी थी, लेकिन इसके उपयोगिता प्रमाणपत्र ही नहीं लिए गए। नगर निगम भोपाल व जबलपुर के आयुक्त और जबलपुर, मुरैना, सिंगरौली जिलों के जनपद पंचायत सीएमओ को लेकर खुलासा किया कि इन्होंने अंत्योष्टि, अनुग्रह राशि एवं विवाह सहायता के नाम पर 2.07 करोड़ रुपए गलत खातों में जमा करवा दिए गए। बोर्ड ने नियमों का उल्ल्घंन करते हुए गैर रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए अंत्योष्टि, अनुग्रह सहायता के नाम पर 2017 से 2022 के बीच 153 मामलों में 5.01 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। इतना ही नहीं अफसरों पर 18.71 करोड़ रुपए को बेकार खर्च करने की बात भी लिखी गई है। रिपोर्ट में बताया कि 2016 में लागू की गई योजना के अनुसार 18.71 करोड़ रुपए की राशि गांव में रहने वाले श्रमिकों की पहचान, वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन पर खर्च की गई लेकिन यह डेटा कभी रजिस्टर्ड नहीं किया गया।भोपाल के वल्लभ भवन और कलेक्ट्रेट के पास 37.69 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर झुग्गी और अवैध निर्माण से सरकार को 322.71 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण इन अतिक्रमणों को समय रहते हटाया नहीं गया, जिससे राजस्व हानि हुई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रशासनिक स्तर पर इस अतिक्रमण को रोकने के लिए पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए। न तो इसे अतिक्रमण पंजी में दर्ज किया गया और न ही संबंधित विभागों को रिपोर्ट भेजी गई। कैग ने अपनी जांच में पाया कि यदि समय रहते यह अतिक्रमण चिह्नित कर लिया जाता, तो इसे हटाने की कार्रवाई हो सकती थी।

इधर, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को अफसरों ने सस्ते में थमा दी जमीन, खजाने को 65.05 करोड़ का नुकसान

भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 20.23 हेक्टेयर सरकारी जमीन दी गई। कैग रिपोर्ट के अनुसार, जमीन की कीमत 218 करोड़ रुपए थी, पर इसे मात्र 38.85 करोड़ रुपए में सौंप दिया गया। कलेक्टर ने इस जमीन का बाजार मूल्य 109 करोड़ रुपए तय किया था, लेकिन पट्टा विलेख 38.85 करोड़ रुपए में किया गया और सिर्फ 9.71 करोड़ (कीमत का 25%) ही प्रीमियम लिया गया। कैग के अनुसार, सही मूल्य नहीं दिखाने से सरकार को 65.05 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

नफरती मंसूबे

अलगाववादियों के एजेंडे को लेकर पश्चिमी देशों की सरकारों के प्रश्रय से मुखर हुए कुछ अराजक तत्वों द्वारा अमेरिका में कैलिफोर्निया स्थित स्वामी नारायण मंदिर पर हमला करना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। वहां आपत्तिजनक संदेश लिखकर मंदिर को क्षति पहुंचायी गई। इससे पहले भी आतंक फैलाने की मंशा से मंदिरों पर हमले होते रहे हैं। जाहिर है ऐसे आपराधिक तत्वों की मंशा आतंक फैलाना ही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कुत्सित कोशिशों की निंदा की है, लेकिन अमेरिकी सरकार द्वारा ऐसे मामलों की अनदेखी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई न करना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। दरअसल, पृथकतावादी तत्व हिंदुओं के खिलाफ विष वमन करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति के अंग-संग रहने वाले समाज को विभाजित करके घृणा का कारोबार करने वाले तत्वों को बेनकाब करने की जरूरत है। विडंबना यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा में सक्रिय ऐसे तत्वों को इन देशों की सरकारों द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर प्रश्रय दिया जाता है। सवाल यह उठता है कि जब ऐसी आजादी किसी सभ्य समाज के अहसासों से खिलवाड़ करे और दूसरों की धार्मिक आजादी का अतिक्रमण करने लगे तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? दरअसल, ये घटनाक्रम इन देशों के दोगले मापदंड उजागर करते हैं। दूसरे देशों में सांप्रदायिक असहिष्णुता और कथित भेदभाव के आंकड़े जारी करके दबाव बनाने वाले तथाकथित सभ्य देश अपने क्रियाकलापों से बेनकाब हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में करीब एक दर्जन मंदिरों को अपवित्र करने की कुत्सित कोशिश हुई, लेकिन ऐसे तत्वों के खिलाफ दिखावे के लिये भी कार्रवाई नहीं की गई। किसी हमले की जांच भी नहीं हुई। जबकि प्रत्येक संप्रदाय की धार्मिक आजादी की रक्षा करना अमेरिकी सरकार का नैतिक दायित्व है। आखिर मंदिरों को सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करायी जाती। बीते साल भी कनाडा में हिंदू महासभा के मंदिर में हमला करके बच्चों व महिलाओं तक को पीटा गया था। लेकिन ट्रुडो सरकार खामोश रही।

विडंबना यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा की सरकारें ऐसे हमलों व मंदिरों को अपवित्र करने की घटनाओं को अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में रखकर आंखें मूंद लेती हैं। लेकिन जब दूसरे देशों में उनके धर्म के लोगों के पूजा स्थलों पर हमले होते हैं तो उसे धार्मिक आजादी व मानवाधिकारों का संकट बताने लगते हैं। निश्चित रूप से ऐसे ही रवैये से भारत के साथ इन देशों के संबंधों में खटास ही आएगी। ऐसे ही अलगाववादियों के कृत्यों व कनाडा सरकार के अलगाववादियों को संरक्षण देने के चलते ही दोनों देशों के संबंध सबसे खराब दौर में पहुंचे हैं। पिछले साल हिंदू महासभा के मंदिर परिसर में मंदिर प्रशासन व भारतीय उच्चायोग द्वारा लगाए गए वीजा शिविर को निशाना बनाया गया था। अभी हाल ही में ब्रिटेन में विदेश मंत्री जयशंकर के काफिले को खालिस्तान समर्थकों ने निशाना बनाया था। इससे पहले दो वर्ष पूर्व भी पृथकतावादियों ने भारतीय उच्चायोग परिसर में घुसकर तिरंगा निकाल दिया था। तब भी भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से कड़ा प्रतिवाद किया था। लेकिन हाल ही में विदेशमंत्री के काफिले को निशाना बनाया जाना बताता है कि ब्रिटिश सरकार की उदासीनता से अलगाववादियों के हौसले बुलंद ही हुए हैं। यहां सवाल ब्रिटिश सरकार पर भी उठता है कि वह विदेशी राजनयिकों को सुरक्षा देने में नाकाम है। इसके अलावा भारत सरकार लगातार अलगाववादियों पर अंकुश लगाने को कहती रहती है। हाल ही में ब्रिटिश गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ऐसे अतिवादियों के उभार को ब्रिटिश कानून व्यवस्था के लिये खतरा बताया गया था। लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामलों की अनदेखी की जा रही है। निश्चित तौर पर छोटी घटनाओं को नजरअंदाज करने से कालांतर बड़ी हिंसक गतिविधियों को ही प्रश्रय मिलता है। यह भी सवाल उठना स्वाभाविक है कि विदेश मंत्री के सामने नारेबाजी कर रहे ऐसे तत्व सुरक्षा घेरे को तोड़कर कैसे विदेशमंत्री की कार के करीब तक पहुंच गए। घटना से स्पष्ट है कि उच्च स्तर पर सुरक्षा में चूक का मामला है। जिसके लिए लंदन पुलिस की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। निश्चित रूप से पश्चिमी देशों की सरकारों को अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा व गरिमा तय करनी होगी।

आखिर क्यों दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध के खिलाफ है केंद्र सरकार?

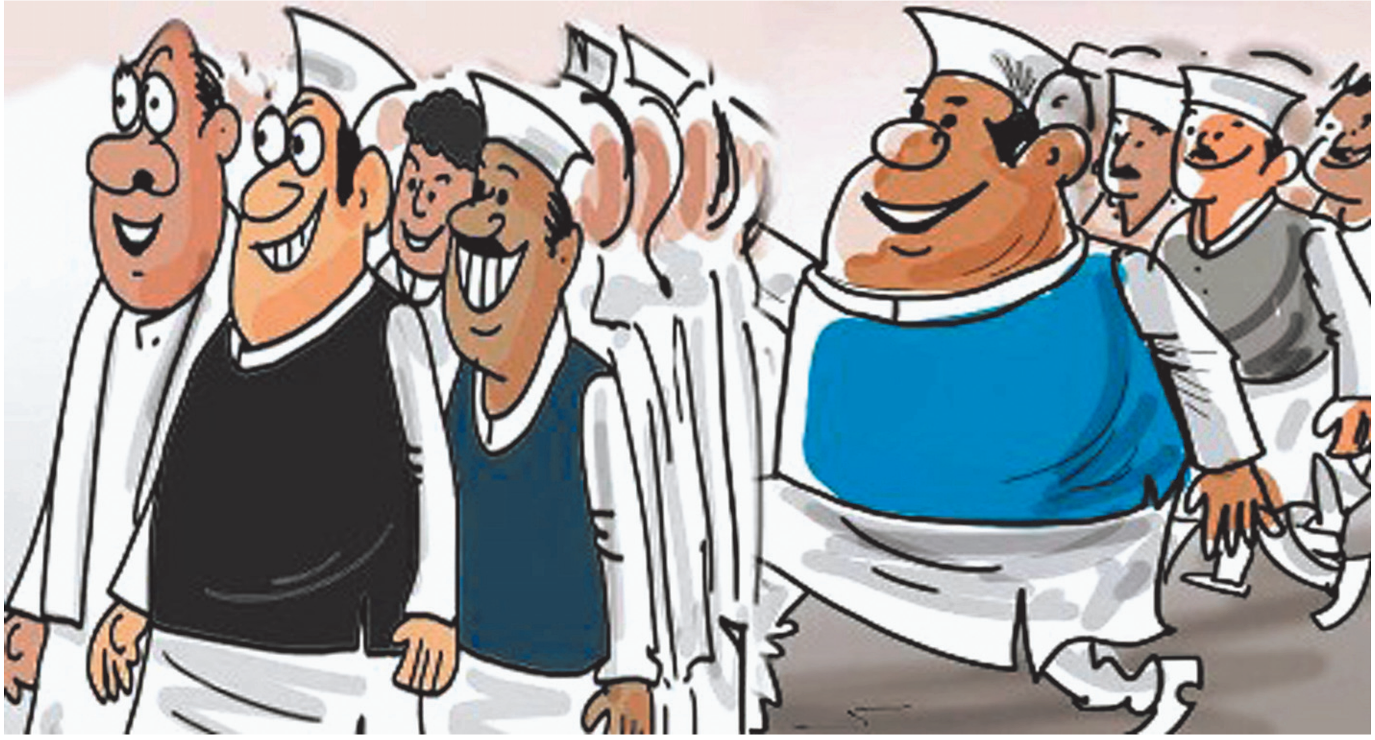

कमलेश पांडेय

ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुद केंद्र सरकार ने ही दोषी करार दिए गए राजनीतिक नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। इससे सरकार की 'बदनीयती' समझ में आती है। एक तो वह समय रहते ही कानून नहीं बनाती है और दूसरे जब इसकी मांग उठती भी है तो अपने पूरे सियासी गिरोह की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तभी तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस तरह की अयोग्यता तय करना केवल संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहां दाखिल अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि अर्जी में जो अनुरोध किया गया है, वह विधान को फिर से लिखने या संसद को एक खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के समान है। चूंकि संविधान ने संसद को अयोग्यता से जुड़े ऐसे अन्य कानून बनाने का अधिकार दिया है, जिसे बनाना वह सही समझता हो।

सरकार के मुताबिक, संसद के पास अयोग्यता के आधार और उसकी समयसीमा, दोनों तय करने की शक्ति है। ऐसे में आजीवन प्रतिबंध लगाना सही होगा या नहीं, यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार का तर्क है कि कानून का स्थापित सिद्धांत है कि दंड या तो समय या मात्रा के अनुसार तय होते हैं। लिहाजा, सजा के असर को एक समय सीमा तक सीमित रखना कोई असंवैधानिक बात नहीं है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 संसद, विधानसभा या विधानपरिषद की सदस्यता के लिए अयोग्यता से सम्बन्धित है।अपने हलफनामे में केंद्र ने रेखांकित किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह कहा है कि एक विकल्प या दूसरे पर विधायी विकल्प के असर को लेकर अदालतों में सवाल नहीं उठाया जा सकता। ऐसे में इस विषय पर न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है! इसलिए कोर्ट विवेकसम्मत व न्यायसंगत निर्देश दे। बता दें कि वर्तमान में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत, किसी भी नेता को सजा होने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाता है। इसलिए केंद्र ने कहा है कि उक्त धाराओं के तहत आजीवन प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा।

इस प्रकार सरकार ने कोर्ट के समक्ष तीन बातें स्पष्ट कर चुकी है। पहला यह कि संविधान ने संसद को अयोग्यता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार दिया है। दूसरा यह कि यह न्यायिक समीक्षा से जुडी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से पूरी तरह से परे है और, तीसरा यह कि दोषी राजनेताओं पर आजीवन बैन सही है या नहीं, यह सवाल पूरी तरह से संसद के दायरे में आता है।इससे साफ है कि सरकार में शामिल राजनीतिक नेतृत्व अपने दूरगामी राजनीतिक हितों के दृष्टिगत राजनेताओं के खिलाफ सही और तर्कसंगत कानून भी नहीं बनने देता है और जब जब ऐसी बात उठती है तो वह तमाम तरह के किंतु-परन्तु करता है। यही वजह है कि हमारी संसद में गरीबों को छोड़कर हर तरह के लोग मिल जाएंगे। गम्भीर अपराध और चरित्रहीनता के आरोपी भी! 'दंगाई' और 'देशद्रोही' भी! क्योंकि कानून राजनेताओं के पक्ष में है, जिसका ये भरपूर लाभ उठाते हैं। एडीआर की रिपोर्ट्स इस बात की पूरी चुगली करती है।

लिहाजा, यह एक गम्भीर प्रशासनिक विडंबना है, संवैधानिक त्रासदी है और समाज में बढ़ते अपराधिक और राजनीतिक मनमानी की सबसे बड़ी वजह भी है। ऐसा इसलिए कि राजनेताओं के खिलाफ यथोचित कानूनों की कमी है। कई मामलों में उन्हें अनैतिक संरक्षण भी विशेषाधिकार के तौर पर हासिल है। ऐसे सभी मामलों में सत्ता पक्ष-विपक्ष चोर चोर मौसेरे भाई की तरह काम करते हैं।

इसलिए भ्रष्ट और दोषी नेताओं के खिलाफ उतनी मुकम्मल कार्रवाई नहीं हो पाती है, जितनी कि आम जनता के खिलाफ तुरंत हो जाती है। क्या अमृतकाल में यह प्रवृत्ति बदलेगी या फिर लोकतांत्रिक हलाहल भी जनता को ही पीने के लिए अभिशप्त रहना होगा, यक्ष प्रश्न है। खासकर लगातार तीन बार केंद्र में सत्तारूढ़ हुई एनडीए के नेतृत्व वाली मोदी सरकार को इससे बचना चाहिए क्योंकि राजनीतिक सुधार के लिए उससे जनता को बहुत उम्मीदें है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक हैं)

> “जब राजनीति से भ्रष्टाचार और अपराध खत्म करने के दृष्टिगत केंद्र सरकार ही गम्भीर नहीं है, तब इसे रूकवा पाना न्यायपालिका के लिए कतई संभव नहीं है। चूंकि केंद्र सरकार अपने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व के इशारे पर हर फैसले लेती है, इसलिए बेलगाम नेताओं को कानूनी नजरिए से बांधने की अधिकांश न्यायिक पहल भी बेकार चली जाती है। सच कहूं तो नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती है। सरकार के मुताबिक, संसद के पास अयोग्यता के आधार और उसकी समयसीमा, दोनों तय करने की शक्ति है। ऐसे में आजीवन प्रतिबंध लगाना सही होगा या नहीं, यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यही वजह है कि हमारी संसद में गरीबों को छोड़कर हर तरह के लोग मिल जाएंगे। गम्भीर अपराध और चरित्रहीनता के आरोपी भी! 'दंगाई' और 'देशद्रोही' भी! क्योंकि कानून राजनेताओं के पक्ष में है, जिसका ये भरपूर लाभ उठाते हैं। एडीआर की रिपोर्ट्स इस बात की पूरी चुगली करती है।”

विपक्षी गठबंधन के रास्ते की बाधा कौन?

चुनाव के सबक की अनदेखी की तो कांग्रेस और सभी प्रादेशिक पार्टियों की मुश्किलें और बढ़ेंगी

नई दिल्ली। भाजपा विरोधी विपक्षी गठबंधन में अभी जो समस्याएं दिख रही हैं क्या उनके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस के कारण राज्यों में विपक्षी गठबंधन यानी 'इंडिया' ब्लॉक कारगर नहीं हो सका? हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद यह सवाल विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाया जा रहा है तो भाजपा विरोधी इकोसिस्टम के राजनीतिक विश्लेषक भी कांग्रेस को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस की दो कदम आगे बढ़ने और एक कदम पीछे हटने की राजनीति के कारण विपक्षी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ी हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले कांग्रेस तमाम समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। प्रादेशिक क्षत्रपों की महत्वाकांक्षा भी इसके लिए जिम्मेदार है तो केंद्र की सत्ता के आगे समर्पण या किसी किस्म के लोभ के कारण भी प्रादेशिक क्षत्रप गठबंधन को कमजोर करने वाले कदम उठा रहे हैं।

अगर कांग्रेस की बात करें तो कह सकते हैं कि पुनर्जीवित होने की उम्मीद ने कांग्रेस की तार्किक सोच को प्रभावित किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जिस स्थिति में थी वह स्थिति बदल गई है। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस को लगने लगा कि उसकी वापसी शुरू हो गई और भाजपा का ढलान आ गया। जैसे कांग्रेस बिना अपवाद के हर चुनाव के बाद जनादेश की गलत व्याख्या करती है वैसे ही इस बार भी किया। इस बार कांग्रेस को यह लगा कि विपक्षी गठबंधन यानी 'इंडिया' ब्लॉक को जो 204 सीटें आई हैं और विपक्ष ऐतिहासिक रूप से मजबूत होकर उभरा है वह उसकी वजह से हुआ है। उसने यह नहीं माना कि उसकी 99 सीटें और विपक्ष की 204 सीटें विपक्षी गठबंधन की सामूहिक ताकत से आई हैं और इसमें प्रादेशिक क्षत्रपों का भी योगदान है। कांग्रेस ने माना कि प्रादेशिक क्षत्रपों को भी जो फायदा हुआ है वह उसकी वजह से हुआ है। दूसरी ओर प्रादेशिक क्षत्रप समझ रहे हैं कि उनकी वजह से कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है।

लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस यह मानने लगी कि देश का मुसलमान अब पूरी शिद्दत के साथ उसके साथ खड़ा है और मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से दलित की वापसी हो रही है। इसके अलावा एक बड़े समूह का भाजपा से मोहभंग हो रहा है और वह कांग्रेस को विकल्प के तौर पर देख रहा है। कांग्रेस ने जून 2024 के बाद इसी सोच में काम किया। इसका नतीजा यह हुआ है कि लोकसभा चुनाव में प्रादेशिक पार्टियों के सामने सरेंडर करके अब तक के सबसे कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी कांग्रेस विधानसभा चुनावों में ज्यादा सीटों के लिए अड़ गई या गठबंधन से इनकार कर दिया।

जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के नतीजों से कांग्रेस का यह भ्रम टूट जाना चाहिए था कि प्रादेशिक पार्टियां उसकी वजह से जीत रही हैं। वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ठीक से तालमेल नहीं हुआ। 90 सीटों की नेशनल कॉन्फ्रेंस 56 और कांग्रेस 38 सीटों पर लड़ी। इस तरह छह सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हुआ। नतीजों में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस 56 में से 42 सीटों पर जीती, जबकि कांग्रेस 38 लड़ कर सिर्फ छह सीटें जीत पाई। उसको पिछली बार से भी छह सीटें कम मिलीं। ऐसे ही महाराष्ट्र में अंतिम समय तक गठबंधन अटका रहा और नतीजा यह हुआ कि पूरा गठबंधन ही साफ हो गया। 288 के सदन में विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 46 सीटें मिलीं।

कांग्रेस ने परिणाम को स्वीकार करने और उसके हिसाब से सुधार करने की बजाय यह कहना और मानना शुरू कर दिया कि मतदाता सूची और ईवीएम में गड़बड़ी से भाजपा का गठबंधन जीता है। अभी तक कांग्रेस यही मान रही है। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के नतीजे के बाद कायदे से कांग्रेस को संभल जाना चाहिए था और हरियाणा व दिल्ली में वापस 'इंडिया' ब्लॉक को पुनर्जीवित करना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आम आदमी पार्टी को अकेले लड़ने दिया। सो, जो हाल हरियाणा का हुआ वही दिल्ली का हुआ। दोनों जगह भाजपा ने सरकार बनाई। झारखंड में जरूर विपक्षी गठबंधन चुनाव जीता लेकिन उसमें कांग्रेस का रत्ती भर योगदान नहीं है। कांग्रेस ने तो टिकटों में जैसी बंदरबांट की थी, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत तेज लहर नहीं होती तो वहां भी भाजपा की सरकार बनती।

जाहिर है विपक्षी गठबंधन कमजोर होने या राज्यों के चुनाव में बिखरने के लिए कांग्रेस काफी हद तक जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रादेशिक क्षत्रपों की जिम्मेदारी कम है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटों के लगभग दोगुना होने का असर यह हुआ कि सभी प्रादेशिक पार्टियां आशंकित हो गईं। उनको कांग्रेस की वापसी की चिंता सताने लगी। उनको लगने लगा कि अगर कांग्रेस पहले की तरह मजबूत होती है तो यह उनके लिए मुश्किल वाली बात होगी। तभी सबने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। एक तरफ कांग्रेस मान रही थी कि उसकी वजह से लोकसभा चुनाव जीते हैं तो दूसरी ओर प्रादेशिक पार्टियां मान रही थीं कि उनके कंधे पर सवार होकर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया।

इस थ्योरी को भाजपा ने भी सपोर्ट किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस परजीवी हो गई है और प्रादेशिक पार्टियों के दम पर जैसे तैसे सांस ले रही है। इस थ्योरी को समझने के लिए सिर्फ एक समाजवादी पार्टी की मिसाल दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में उसने कांग्रेस से तालमेल किया और 37 सीटें जीती। वहां दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। इस ऐतिहासिक नतीजे के बाद दोनों एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगे। कांग्रेस को लेकर ऐसा संदेह बाकी प्रादेशिक पार्टियों में भी दिखा।

तभी अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी और लालू प्रसाद से लेकर शरद यादव व उद्धव ठाकरे तक नेतृत्व बदलने के ममता बनर्जी के राग का समर्थन करने लगे। कहा जाने लगा कि ममता बनर्जी को नेता बनाया जाए। इनमें से किसी ने समझदारी की बात नहीं की और न विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखने का प्रयास किया। उलटे सबने आग में घी डालने का काम किया। अगर प्रादेशिक पार्टियों के नेता गठबंधन बचाने का प्रयास करते तो वे हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल करा सकते थे। वे यह बात भी भूल गए कि विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर ले आने और 'इंडिया' ब्लॉक का गठन करने में एक प्रादेशिक क्षत्रप नीतीश कुमार ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी।इसलिए ऐसा नहीं था कोई बड़ा प्रादेशिक नेता पहल करता तो कांग्रेस उसकी बात नहीं सुनती।

क्या इंडिया गठबंधन भंग कर देना चाहिए? नेतृत्व के लिए राहुल गांधी सबसे मुफीद?

पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों में कमी के बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद थे, लेकिन उसके बाद कुछ राज्यों के चुनाव में हार से अब उनके अंदर खटपट बढ़ गई है। इंडिया टुडे-सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में ज्यादातर लोगों ने गठबंधन को जारी रखने के पक्ष में राय दी है। गठबंधन का नेतृत्व किसे करना चाहिए,इसके जवाब में ज्यादातर ने राहुल गांधी का नाम लिया।राज्यों में एक के बाद एक हार के साथ ही, इंडिया गठबंधन में खटपट भी तेज होती गई है। इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन को अब भंग कर देना चाहिए? या जारी रहना चाहिए? इसका नेतृत्व किसके हाथ में रहना चाहिए? इन सवालों पर जनता क्या सोचती है, इस जवाब इंडिया टुडे के 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे में मिला है।

65 प्रतिशत लोग इंडिया गठबंधन जारी रखने के पक्ष में

सर्वे में शामिल 65 प्रतिशत लोगों ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को इंडिया गठबंधन को जारी रखना चाहिए। हालांकि, 26 प्रतिशत का मानना था कि इस गठबंधन को अब भंग कर देना चाहिए।

इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए राहुल पहली पसंद, ममता दे रहीं टक्कर

सर्वे में जब ये पूछा गया कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए कौन सा नेता सबसे मुफीद है तो सबसे ज्यादा प्रतिभागियों ने राहुल गांधी का नाम लिया। इस मामले में उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टक्कर देती दिख रही हैं। सर्वे में शामिल, 24 प्रतिशत लोगों ने कहा कि गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में होना चाहिए। 14 प्रतिशत का कहना था कि ममता बनर्जी के हाथ में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व होना चाहिए। 9 प्रतिशत लोगों ने अरविंद केजरीवाल तो 6 प्रतिशत लोगों ने अखिलेश यादव का नाम लिया।

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार

मोदी का पाकिस्तान को करारा जवाब

आतंकवाद फैलाने का लगाया आरोप

मार्च की 16 तारीख की शाम को पीएम नरेंद्र मोदी और लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट जारी हुआ। 3 घंटा 17 मिनट के इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने वैश्विक राजनीति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, भारत की विकास यात्रा और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब दिए हैं। एक ओर पीएम मोदी के इस इंटरव्यू को जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वहीं, दूसरी तरफ इंटरव्यू में चीन को लेकर पीएम मोदी की 'सकारात्मक टिप्पणियों' की, शी जिनपिंग सरकार ने भी सराहना की है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, 'चीन-भारत संबंधों पर प्रधानमंत्री मोदी की हालिया सकारात्मक टिप्पणी सराहनीय है।' दरअसल, इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने भारत-चीन संबंधों पर बात की थी और कहा था- 'दो पड़ोसी देशों के बीच मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि ये मतभेद विवाद में न बदले।' इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने वैश्विक राजनीति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, भारत की विकास यात्रा और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब दिए हैं। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'यह मेरे जीवन की सबसे मार्मिक और शक्तिशाली बातचीत में से एक थी।' फ्रीडमैन, पीएम मोदी से पहले दुनिया के सबसे बड़े अरबपति एलन मस्क, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जैसे बड़े नेताओं का भी इंटरव्यू ले चुके हैं। इस इंटरव्यू में गोधरा से लेकर पाकिस्तान तक, जिन बड़े और गंभीर मुद्दों पर बात की है, अब एक-एक कर उनके बारे में जानते हैं-

लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा...

संघ से मुझे जीवन के संस्कार मिले

अमेरिकी पॉडकास्टर के इंटरव्यू में ट्रंप और चीन पर पीएम मोदी के 5 छिपे संदेश

पेज-8 पर

उपवास रखने और हिंदू धर्म पर

पॉडकास्ट की शुरुआत में फ्रीडमैन ने कहा, 'मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने उपवास रखा है। अब वैसे 45 घंटे यानी दो दिन हो गए हैं। मैं सिर्फ पानी पी रहा हूं, खाना बंद है। मैंने ये इस बातचीत के सम्मान और तैयारी के लिए किया है ताकि हम अध्यात्म वाले तरीके से बात करें।' इसके बाद फ्रीडमैन ने पीएम मोदी से सवाल पूछा- 'मैंने सुना है कि आप भी अक्सर काफी उपवास रखते हैं। क्या आप उपवास रखने का कारण बताएंगे?' इसके जवाब पीएम मोदी ने कहा, 'मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है कि आपने उपवास रखा और वो भी उस भूमिका से रखा कि जैसे मेरे सम्मान में हो रहा हो। भारत में जो धार्मिक परंपराएं हैं, वो दरअसल, जीवनशैली हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की बहुत बढ़िया व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू धर्म किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, लेकिन ये Way of Life है, जीवन जीने की पद्धति है।'

अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर

अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े सवाल पर जवाब देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन के स्टेडियम में हाउडी मोदी के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा, 'भाषण के बाद मैंने जब ट्रंप से पूछा कि क्या स्टेडियम का चक्कर लगाएं तो वे तुरंत तैयार हो गए। अमेरिका का सुरक्षा तंत्र बेचैन हो गया।आप जानते ही हैं कि सुरक्षा कितनी कड़ी होती है। कितनी जांच होती है। मेरे लिए यह बात दिल को छू गई कि इस व्यक्ति में हिम्मत है। वह फैसले खुद लेते हैं और दूसरा उनको मोदी पर भरोसा है कि मोदी उनको ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं।ट्रंप ने उन्हें सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपना सारा भवन दिखाया। वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं और मैं भारत फर्स्ट वाला हूं। हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है।'

बचपन के दिनों की गरीबी को याद कर क्या बोले पीएम मोदी?......

बचपन को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर फ्रीडमैन को कहा, 'मेरा जीवन अत्यंत गरीबी में बीता था लेकिन हमने कभी गरीबी का बोझ महसूस नहीं किया। क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है, उसके पास जूते नहीं हैं तो उसे लगता है कि ये कमी है, लेकिन हमने तो कभी जिंदगी में जूते पहने ही नहीं थे। तो हमें क्या मालूम था कि जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। हम तो कंपेयर करने की हालत में ही नहीं थे।' इसके आगे उन्होंने कहा, 'मुझे याद है कि मेरे तो कभी स्कूल में जूते पहनने का सवाल ही नहीं था। एक दिन में स्कूल जा रहा था, मेरे मामा रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा 'अरे, तू ऐसे स्कूल जाता है, जूते नहीं है'। तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीदकर मुझे पहना दिए। तब उनकी कीमत 10–12 रुपए होगी। वह जूते कैनवास के थे उस पर दाग लग जाते थे, तो मैं ये करता था कि जब शाम को स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था। और टीचर जो चॉकस्टिक का उपयोग करके उनके टुकड़े फेंक देते थे, उन्हें एकत्र करके घर ले आता था। उन चॉकस्टिक के टुकड़ों को भिगोकर, पॉलिश बनाकर कैनवास के जूते पर लगाकर चमकदार सफेद बना लेता था। मेरे लिए वही संपत्ति थी।

आरएसएस से जुड़ाव पर

लेक्स फ्रीडमैन ने पीएम मोदी से पूछा– 'जब आप आठ साल के थे, तब आरएसएस में शामिल हो गए थे, जो हिंदू राष्ट्रवाद के विचार का समर्थन करता है। क्या आप मुझे आरएसएस के बारे में बता सकते हैं?' इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे याद है कि मकोशी नाम का एक आदमी था, मुझे उनका पूरा नाम ठीक से याद नहीं है, मुझे लगता है कि वे सेवा समूह का हिस्सा थे। वे एक ढफली बजाकर देशभक्ति गीत गाते थे। मुझे वह गीत सुनने में मजा आता था, इसलिए मैं पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ता रहता था। हमारे गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा थी, जहां देशभक्ति के गीत चलते थे। उन गीतों की कुछ बातें मुझे बहुत छू गईं और इस तरह मैं आरएसएस का हिस्सा बन गया।' इसके आगे उन्होंने कहा, 'संघ दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। यह अब अपनी 100वीं वर्षगांठ के करीब है। करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। स्वयंसेवकों को कहा जाता है कि तुम्हें जो संघ से प्रेरणा मिली है, उससे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आज उस भावना से प्रेरित होकर कई पहल चल रही हैं। जैसे कुछ स्वयंसेवकों ने सेवा भारती नामक संगठन की स्थापना की। यह संगठन उन झुग्गी–झोपड़ियों और बस्तियों की सेवा करता है जहां सबसे गरीब लोग रहते हैं, जिन्हें वे सेवा समुदाय कहते हैं।संघ से जुड़े वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासी समुदायों की सेवा के लिए समर्पित हैं। वे आदिवासियों के बीच रहते हैं, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। उन्होंने दूरदराज के आदिवासी इलाकों में 70,000 से ज़्यादा एक शिक्षक वाले स्कूल खोले हैं। आप देखेंगे कि पिछले 100 साल में आरएसएस ने भारत की चकाचौंध से दूर रहकर एक साधक की तरह समर्पित भाव से काम किया है। मेरे सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र सगंठन से मुझे जीवन के संस्कार मिले।'

पाकिस्तान के साथ रिश्ते पर क्या बोले पीएम मोदी

पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में पीएम मोदी ने कहा, 'दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की घटना घटती है। सूत्र कहीं न कहीं पाकिस्तान पर जाकर अटकते हैं। अमेरिका में 9/11 की इतनी बड़ी घटना घटी। उसका मुख्य सूत्रधार ओसामा बिन लादेन आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में शरण लेकर बैठा था। पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए नहीं दुनियाभर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। हम लगातार उसको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा। आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद बंद होना चाहिए।' फ्रीडमैन के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, 'शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को खास तौर से आमंत्रित किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। हर बार अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले।' पीएम मोदी ने आगे कहा कि वहां की आवाम भी दुखी हो गई है, ऐसा मैं मानता हूं। इस प्रकार की लहू–लुहान, मारकाट से पाकिस्तान के लोग भी परेशान हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अपना पाने के बाद उन्हें लगना चाहिए कि हमें हमारा मिल गया, भारत का धन्यवाद करें। लेकिन उन्होंने भारत के साथ लगातार संघर्ष का रास्ता चुना।

गोधरा दंगा और खुद पर लगे आरोपों पर

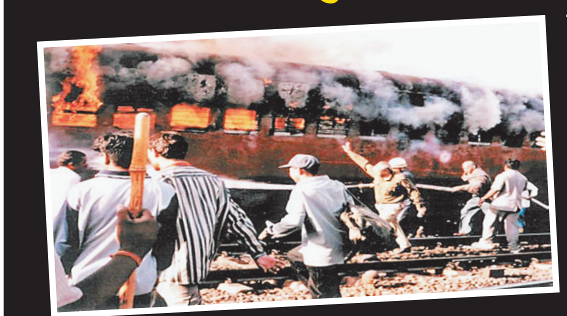

पीएम मोदी ने गोधरा दंगे पर फ्रीडमैन के सवाल पर कहा, 'मैं इस दंगे से पहले की तस्वीर आपको बताना चाहूंगा। 24 दिसंबर 1999 विमान हाईजैक कर कंधार ले जाया गया। 2000 में दिल्ली में लाल किले पर आतंकी हमला हुआ। उस समय आठ से दस महीनों के बीच की घटनाएं देखिए। ऐसे में मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला। उससे पहले शताब्दी का सबसे बड़ा भूकंप आया था। मैं शपथ लेने के साथ ही इस काम में जुट गया। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम सदन में बैठे थे और उसी दिन विधायक बने हमें तीन दिन हुए थे कि गोधरा की घटना हो गई। यह भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। कंधार विमान से शुरू होकर कई बड़ी घटनाओं की पृष्ठभूमि और उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना। आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसे होगी?जो ये कहते हैं कि बहुत बड़ा दंगा था तो यह भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 से पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे? पतंग के चक्कर में सांप्रदायिक हिंसा हो जाती थी। साइकिल टकराने पर सांप्रदायिक हिंसा हो जाती थी। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे। 1969 में जो दंगे हुए थे वह छह महीने तक चले थे। इतनी बड़ी घटना स्पार्किंग प्वाइंट बन गई और कुछ लोगों की हिंसा में मौत हो गई।'

यूक्रेन-रूस जंग पर

रूस–यूक्रेन जंग पर फ्रीडमैन के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, 'हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं, तो विश्व हमें सुनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। मेरे रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं।मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने यह कह सकता हूं कि यह युद्ध का समय नहीं है और एक मित्र भाव से जेलेंस्की को भी कहता हूं कि दुनिया कितनी भी आपके साथ खड़ी क्यों न हो जाए रणभूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ बैठकर कितनी भी बातचीत कर ले, दोनों पक्ष का होना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं शांति के पक्ष में हूं।'

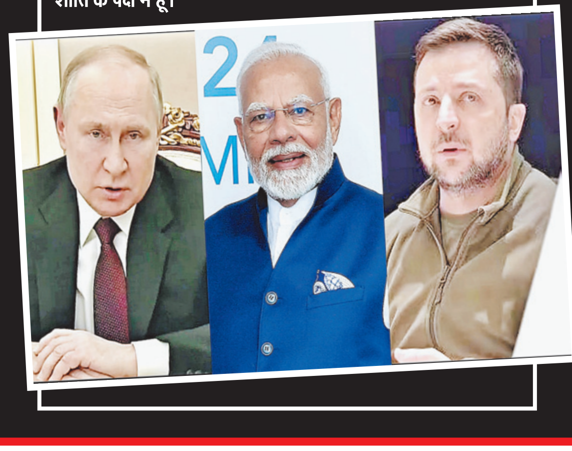

अपने निर्णय लेने की क्षमता पर

नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे बड़े और चुनौतिपूर्ण निर्णय लेने के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, 'शासन की दृष्टि से देखें तो मेरे पास कोई बोझ नहीं है। निर्णय करने में मेरा एक तराजू है कि मेरा देश सबसे पहले। सिर्फ अफसरों की नहीं सुनता, उनसे सवाल भी करता हूं। ताकि बातचीत से सही फैसला निकले। मेरी जोखिम लेने की क्षमता बहुत है। मैं ये नहीं सोचता कि मेरा क्या नुकसान होगा। जो देश के लोगों के लिए सही है, वहां मैं जोखिम लेने को तैयार रहता हूं। अगर कुछ गलत हो जाए तो खुद उसका जिम्मा लेता हूं।'

एआई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर

प्रधानमंत्री ने एआई से जुड़े एक सवाल पर कहा, ' दुनिया एआई के लिए कुछ भी कर ले लेकिन भारत के बिना एआई अधूरा है। मेरा मानना है कि एआई विकास मूलत: एक सहयोग है। इसमें शामिल सभी लोग साझा अनुभवों और सीख के जरिये एक–दूसरे का समर्थन करते हैं। भारत सिर्फ इसका मॉडल नहीं बना रहा, बल्कि इसके विशेष उपयोग के मामलों के हिसाब से एआई आधारित एप्लिकेशन को भी विकसित कर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शक्तिशाली है लेकिन यह कभी भी मानव कल्पना की गहराई से मेल नहीं खा सकती।'

विदेश नीति और चीन के साथ संबंधों पर

पीएम मोदी ने चीन और विदेश नीति के सवाल पर कहा, 'जब 2013 में उन्हें पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो लोग कह रहे थे कि उसने एक राज्य चलाया है और उसको विदेश नीति क्या समझ में आएगी। तब मैंने कहा था कि भाई एक इंटरव्यू में पूरी विदेश नीति तो समझा नहीं सकता हूं लेकिन मैं आपको इतना कहता हूं कि हिंदुस्तान न आंख झुकाकर बात करेगा, न आंख उठाकर बात करेगा लेकिन अब हिंदुस्तान आंख में आंख मिलाकर बात करेगा। आज भी मैं उस विचार को लेकर चलता हूं।' चीन के साथ संबंधों पर पीएम मोदी ने कहा, 'दोनों देशों के बीच सदियों पुराने रिश्तें है और एक ज़माने में दुनिया के जीडीपी में आधा हिस्सा भारत और चीन का हुआ करता था। दोनों देशों के बीच संघर्ष का कोई इतिहास नहीं रहा है। इन संबंधों को ऐसे ही मजबूत और जारी रहना चाहिए। दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ न कुछ होता है। कभी कभार असहमति भी स्वाभाविक है। यह परिवार में भी रहता है लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे मतभेद विवाद में न बदलें। 2020 में सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अभी राष्ट्रपति शी के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो स्थिति थी वो सामान्य स्थिति में आ चुकी है।'

अमेरिकी पॉडकास्टर के इंटरव्यू में

ट्रंप और चीन पर पीएम मोदी के 5 छिपे संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन को दिए 3 घंटे 17 मिनट 33 सेकेंड के वीडियो में कई संदेश छिपे हैं। जीवन दर्शन से लेकर कूटनीति तक। दुनिया में टैरिफ वॉर से उथल-पुथल मचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने इशारा किया कि अमेरिका और भारत के संबंध कैसे रहने वाले हैं। सीमा पर अपने तेवर नरम करते चीन को लेकर भी इशारों-इशारों में रिश्तों की रेखा खींची। समझिए इंटरव्यू में ट्रंप और चीन को लेकर आखिर पीएम मोदी का संदेश क्या है।

मोदी ने कहा, भारत और चीन का संबंध आज का नहीं है। दोनों पुरातन संस्कृति हैं। आधुनिक दुनिया में भी दोनों की बड़ी भूमिका है। पुराने रेकॉर्ड देखेंगे तो सदियों तक भारत और चीन एक दूसरे से सीखते रहे हैं। दोनों मिलकर दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई योगदान देते रहे हैं। दुनिया का जो जीडीपी था, उसका अकेले 50 प्रतिशत भारत और चीन का हुआ करता था। पहले की सदियों में भारत और चीन के बीच संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। बुद्ध का प्रभाव काफी रहा है। भारत से ही वह विचार गया है। भविष्य में भी इन संबंधों को ऐसा ही मजबूत रहना चाहिए। मतभेद होते हैं। परिवार में भी रहता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि यह मतभेद विवाद में न बदलें। हम बातचीत पर बल देते हैं, तभी एक स्थायी और सहयोगी रिश्ते बनते हैं। यह ठीक है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। 2020 में जो सीमा पर घटना घटी, उससे हमारे बीच दूरियां बढ़ीं। अभी हाल में राष्ट्रपति शी के साथ मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद सीमा पर चीजें सामान्य हो रही हैं। धीरे-धीरे वह उत्साह और उमंग वापस आ जाए। इसमें समय लगेगा। दोनों मुल्कों का साथ होना दुनिया की स्थिरता के लिए भी जरूरी है।

ट्रंप के बड़प्पन की बात ....

पीएम मोदी ने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट का जिक्र कर ट्रंप के साथ अपने रिश्तों की गर्माहट को समझाया। उन्होंने कहा कि वह मंच से भाषण दे रहे थे और अमेरिका के राष्टपति ट्रंप नीचे बैठकर सुन रहे थे। यह सम्मान दिल छू लेने वाला था। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने ट्रंप से स्टेडियम का चक्कर लगाने का अनुरोध किया, जो उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर बिना कुछ सोचे स्वीकार कर लिया।

1- ट्रंप को मोदी पर भरोसा है

पीएम मोदी ने कहा हाउडी मोदी कार्यक्रम ने उनके दिल को छू लिया। उन्हें उसी दिन लग गया था कि इस व्यक्ति में हिम्मत है। यह फैसले खुद लेते हैं। दूसरा मोदी पर उनको भरोसा है। मोदी ले जा रहा है, तो चलिए चलते हैं। यह आपसी विश्वास का भाव है।

2- हमारी जोड़ी जम जाती है

पीएम मोदी ने कहा कि हाउडी मोदी में ट्रंप का विश्वास और राष्टपति चुनाव में जब उन पर गोली चली, तो दोनों राष्टपति ट्रंप एक ही नजर आए। स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़कर चलने वाले ट्रंप और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए ही जिंदगी वाला भाव। मैं नेशन फर्स्ट वाला हूं, वह अमेरिका फर्स्ट वाले हैं। हमारी जोड़ी जम जाती है।

3- ट्रंप अमेरिकी मूल्यों का सम्मान करते हैं

मैं जब पहली बार वाइट हाउस गया, तो राष्टपति ट्रंप के बारे में मीडिया में बहुत कुछ छपता था। मुझे भी भांति भांति का ब्रीफिंग की गई थी। जब मैं वाइट हाउस पहुंचा तो पहले मिनट में उन्होंने सारे प्रोटोकॉल की दीवारें तोड़ दीं। जब वह मुझे घुमाने ले गए तो, उन्होंने जिस बारीकी से मुझे वाइट हाउस के बारे में तारीखवार बातें बताईं, मैं हैरान रह गया। यह बताता था कि वह संस्थान का कितना आदर करते हैं। अमेरिका के इतिहास के साथ उनका कितना लगाव और सम्मान है।

4- ट्रंप से यारी पक्की है

पहली टर्म के बाद जब बाइडन चुनाव जीते, तब भी हमारी रिश्तों की गर्माहट बनी रही। इन चार सालों में उन्होंने पचासों बार कहा कि मोदी मेरे दोस्त हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राष्टपति ट्रंप इस बार पूरी तैयारी के साथ हैं। उन्हें क्या करना है, यह उनको अछे से पता है। उनकी टीम शानदार है। ट्रंप की टीम के जिन लोगों से मैं मिला, सभी से पारिवारिक माहौल में बात हुई।

5- चीन के लिए संदेश क्या है

पीएम मोदी ने चीन को लेकर संदेश दिया कि दोनों मुल्क अगर मिल जाएं, तो दुनिया बदली जा सकती है। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था, जब पूरी दुनिया की जीडीपी में आधी हिस्सेदारी अकेली भारत और चीन की थी।

पीएम मोदी के इंटरव्यू से पाकिस्तान खफा चीन खुश

अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को दिए इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान से शांति की हर कोशिश का परिणाम नकारात्मक निकला है ।पीएम मोदी ने कहा था कि वह शांति की कोशिश में ही लाहौर चले गए थे और 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को न्योता दिया था ।पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसका सूत्र पाकिस्तान से निकल आता है ।अब पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताते हुए प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री की टिप्पणी तथ्यों से परे है और एकतरफ़ा है। उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से जम्मू-कश्मीर विवाद को छोड़ दिया जबकि अब भी पिछले सात दशकों से इसका कोई समाधान नहीं मिला है। ऐसा तब है, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों को आश्वस्त किया था ।प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को ख़ारिज करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, ख़ुद को पीड़ित बताने के लिए भारत काल्पनिक नैरेटिव गढ़ता है लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंकवाद को शह देने के आरोप से बच नहीं सकता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बदले भारत को विदेशी ज़मीन पर आतंकवाद की साज़िश और टारगेटेड किलिंग का अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से नतीजे हासिल करने वाले संवाद की वकालत करता रहा है, जिनमें जम्मू-कश्मीर का विवाद भी शामिल है।

हालांकि इसी इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने चीन के लिए जो कहा, वो बिल्कुल अलग है और चीन के विदेश मंत्रालय ने इसका स्वागत किया है ।पीएम मोदी ने चीन को लेकर कहा, हमारी कोशिश है कि चीन के साथ मतभेद कलह में ना बदले। 2020 में सीमा पर जो घटना घटी, उससे हमारी दूरियां बढ़ गई थीं। लेकिन राष्टपति शी जिनपिंग से मुलाक़ात के बाद सीमा पर स्थिति सामान्य हो रही है। चीन और भारत के बीच स्पर्धा स्वाभाविक है लेकिन संघर्ष नहीं होना चाहिए ।चीन के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की इस टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा, भारत-चीन संबंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकारात्मक बयान का चीन स्वागत करता है।

पिछले साल अक्तूबर में रूस के कज़ान में पीएम मोदी और राष्टपति शी जिनपिंग की मुलाक़ात हुई थी और इस मुलाक़ात से द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक रणनीतिक मार्गदर्शन मिला था ।चीन को लेकर पीएम मोदी की भाषा बिल्कुल अलग थी और पाकिस्तान को लेकर बिल्कुल अलग। ज़ाहिर है इसी के आधार पर दोनों देशों के विदेश मंत्रालय ने जवाब भी दिया है।

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार
इंदौर
30 मार्च 2025

गुजरात होगा नया कुरुक्षेत्र!

» राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमियों को स्वीकारा और सुधार का वादा किया » गुजरात में नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया

अहमदाबाद। राहुल गांधी ने अपने हालिया गुजरात दौरे में बड़ा बम फोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि गुजरात कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो पार्टी को 20 से 30 लोगों को निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। राहुल गांधी की इस बात से कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैरान हैं। कई लोगों को उनकी 2013 वाली बात याद आ गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस को इस तरह बदलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। वह बदलाव कभी नहीं आया।.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सामने जिस तरह से कांग्रेस के जीतने का दावा किया था, लगता है कि कांग्रेस गंभीरतापूर्वक उस दिशा में आगे बढ़ना तय कर चुकी है। कम से कम राहुल गांधी के हालिया दो दिन के गुजरात दौरे से तो यही नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उन्होंने पहले दिन संगठन के लोगों के साथ मैराथन मीटिंग की, उन्हें खूब सुना और अपने मन की बात कहीं। वहीं कार्यकर्ताओं के सामने जब राहुल बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बड़ी साफगोई से वर्कर्स के सामने अपनी पार्टी की कमियों को स्वीकारा तो वहीं उन्होंने अपने लोगों को जनता के बीच जाकर काम करने और पार्टी विचारधारा के दूर खड़े नेताओं को लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत पर जोर दिया ।राहुल के संबोधन से साफ लगता है कि वह प्रदेश में कांग्रेस की कमियों, दिक्कतों और कमजोरियों को न सिर्फ बखूबी समझ व पहचान रहे हैं, बल्कि ईमानदारी से उसे ठीक करने की दिशा में भी काम करना चाहते हैं। अपने संबोधन में राहुल ने जहां अपने लोगों की कमियों को स्वीकारा, वहीं उन्होंने उस पर खुलकर बात की।

ऐक्शन मोड में राहुल गांधी: राहुल ने अपने पार्टी में बीजेपी से प्रभावित या उससे मिले लोगों की बात स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी में बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से कटे हुए और दूर बैठे लोग हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को पार्टी के भीतर बीजेपी की बी टीम करार देते हुए कहा कि सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। उन्होंने गुजरात कांग्रेस में दोनों तरह के कांग्रेस के बीच छंटाई की बात कही। तभी राहुल ने संकेत दिया कि अगर 10-20 ही नहीं 30-40 लोग भी निकालने पड़े तो निकालेंगे, ताकि कांग्रेस की नया स्वरूप लोगों में भरोसा पैदा कर सके। उनका दोटूक कहना था कि अगर बीजेपी के लिए काम करना है तो वहीं जाओ।

नई लीडरशिप पर राहुल का फोकस: सूत्रों के अनुसार, गुजरात में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। एक नेता ने कहा कि गुजरात में महाराष्ट्र जैसा प्रयोग हो सकता है। जिग्नेश मेवाणी और सेवा दल प्रमुख लालजी देसाई के नामों पर चर्चा चल रही है। मेवाणी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन उन्हें एक लोकप्रिय दलित युवा नेता माना जाता है। एक और मुद्दा है जिस पर कांग्रेस नेता और दूसरे लोग राहुल गांधी से नाराज हैं। वह है फैसले लेने में देरी। जैसे कि इंडिया ब्लॉक का क्या होगा? कुछ सहयोगी दल इस पर कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर दलों के अलग-अलग राय हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा की तरह लापरवाह दिख रही है ।वहीं राहुल गांधी ने गुजरात में नई लीडरशिप को आगे बढ़ाने की बात भी कही। उनका कहना था कि बीजेपी समर्थित लोगों के जाने के बाद पार्टी में नए नेता सामने लाए जाएंगे, जिनमें बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक, जिला व प्रदेश स्तर के नेता तक शामिल होंगे। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन अपने नेताओं को आगे बढ़ाने की उनकी शर्त थी कि उन्हीं नेताओं को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, जिसके दिल में कांग्रेस यानी उसकी विचारधारा होनी चाहिए। संगठन का कंट्रोल ऐसे लोगों को ही मिलना चाहिए।

पार्टी नेताओं का दे दिया सख्त संदेश

राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी का पहला काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के दो समूहों को अलग करना है। पहला जो पार्टी की विचारधारा को अपने दिल में रखते हैं और जनता के साथ खड़े हैं और दूसरे जो जनता से कटे हुए हैं। इनमें से आधे बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात कांग्रेस में नेतृत्व और कार्यकर्ता स्तर पर दो तरह के लोग हैं। एक वो जो लोगों के प्रति ईमानदार हैं, वे उनके लिए लड़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। और दूसरे वो हैं, जो लोगों से कटे हुए हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं और उनमें से आधे बीजेपी के साथ हैं।

खरगे से कमान वापस ले रहे हैं राहुल?

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की यह बात और हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) में हुए फेरबदल से लगता है कि वो धीरे-धीरे पार्टी की कमान फिर से अपने हाथों में ले रहे हैं। लगभग तीन साल पहले नेहरू-गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खरगे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। तब उन्होंने तय किया था कि खरगे पार्टी चलाएंगे और परिवार पर्दे के पीछे से मदद करेगा। ऐसा लगता है कि खरगे भी राहुल के हस्तक्षेप से बिल्कुल नाखुश नहीं हैं ।एक कांग्रेस नेता ने कहा, 'राहुल गांधी हमेशा से पार्टी में अहम फैसले लेते रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि वो अपने लोगों को सीधे तौर पर जिम्मेदारी देना चाहते हैं। ये ज्यादातर युवा नेता हैं, जिन्हें वो ईमानदार और मजबूत विचारधारा वाला मानते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि इससे यह भी पता चलता है कि उन्हें दूसरे नेताओं पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा, राहुल गांधी के काम करने के तरीके में अब भी स्पष्टता की कमी दिखती है। पार्टी की दिशा, मुद्दे और संगठन को लेकर कोई साफ राय नहीं है।

कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे राहुल

राहुल ने अपने लोगों से साफ कहा कि अगर आपको जनता का भरोसा जीतना है तो पहले उनके बीच जाकर उनसे बात कीजिए, उनके समस्याओं को उठाएं, उनकी लड़ाई लड़ें, उनके हक की बात करें, तभी जनता का भरोसा जीत पाएंगे। साथ ही, उन्होंने अपने लोगों से कहा कि उन्हें गुजरात व उसके लोगों के लिए यह सब किसी स्वार्थ या लालच के चलते नहीं करना होगा, ना ही वोट के लिए लोगों के बीच जाने की बात सोचनी चाहिए।

तेलंगाना का जिक्र कर कही ये बड़ी बात

राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए तेलंगाना का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी अपने वोट प्रतिशत में पांच फीसदी की भी बढ़ोतरी करने में सफल होती है, तो वह गुजरात में सत्ता में आ सकती है। तेलंगाना में पार्टी अपने वोट प्रतिशत में 22 फीसदी की बढ़ोतरी करने में सफल रही और सत्ता में आई। राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे मुद्दे को उठाया वो बेहद अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस कई राज्यों में गुटबाजी से परेशान है। इसके चलते उसे कई राज्यों में मजबूत उपस्थिति के बावजूद उसे हार का सामना करना पड़ रहा।

'....जनता ये देख रही हैं'

दूसरी ओर राहुल ने ईमानदारी से स्वीकारा कि कांग्रेस ने गुजरात के लोगों को निराश किया है, पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। राहुल का कहना था कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर से लेकर ऊपर तक नेता बब्बर शेर हैं, लेकिन पीछे से चेन लगी हुई है तो वे बंधे हैं। जनता ये देख रही है। इसीलिए उनपर भरोसा नहीं कर पा रही। राहुल ने अपने लोगों से साफ कहा कि कांग्रेस के लोग न सिर्फ जनता से दूर हुए, बल्कि उन्होंने जनता के मुद्दों को लेकर आवाज उठाना भी छोड़ दिया। इसलिए जनता उनसे दूर हुई, पार्टी ने विश्वास खोया।

कांग्रेस के भीतर दो गुट, गुटबाजी पर राहुल गांधी की खरी-खरी

क्या कांग्रेस में जल्द ही बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं? क्या कांग्रेस से जल्द ही कुछ नेताओं को निकाला जा सकता है? क्या गुटबाजी से परेशान कांग्रेस नेतृत्व आने वाले समय में कोई बड़ा एक्शन लेने की सोच रही? ये सवाल उस समय उठे है जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुजरात दौरे पर अपनी ही पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के पहचान करने की जरूरत है, जो बीजेपी के लिए काम कर रहे। उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी ।गुजरात दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर दो गुट नजर आ रहे। आधे लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे। ऐसे लोगों को हटाने की सख्त कार्रवाई करनी पड़े तो जरूर किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने गुजरात की बात करते हुए एक तरह से उन राज्यों के नेताओं को भी सख्त संदेश दे दिया जहां पर गुटबाजी बात अकसर सामने आती रहती है। केरल, कर्नाटक, हरियाणा, एमपी, पंजाब समेत कुछ ऐसे राज्य रहे हैं जहां पार्टी के भीतर झगड़े की बात समय पर कही जाती है।

NDA गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया!

बिहार में बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी भाजपा

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार राजग की ओर से भले ही सीएम पद के घोषित उम्मीदवार होंगे, लेकिन गठबंधन में धमक भाजपा की दिखेगी। सीट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तय करने तक, सभी मामलों की कमान भाजपा के हाथों में होगी। भाजपा इस बार न सिर्फ जदयू से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि चुनावी रणनीति की कमान भी अपने पास रखेगी। इसके अलावा चुनाव प्रचार की पिच पर पीएम मोदी गठबंधन का मुख्य चेहरा होंगे।गठबंधन में दलों की भरमार और पुराने प्रदर्शन के आधार पर जदयू को इस बार भाजपा से कम सीटें मिलेंगी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान परिस्थितियों में जदयू के लिए अधिकतम 90 सीटों से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। भाजपा की कोशिश बीते चुनाव की तरह ही 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। बाकी बची 43 सीटें दूसरे सहयोगियों लोजपा (आर), आरएलएसपी और हम में बंटेंगी। चूंकि लोजपा (आर) ने लोकसभा चुनाव में अपने हिस्से की सभी पांच सीटें जीती हैं, ऐसे में जदयू-भाजपा के इतर सीट बंटवारे में सर्वाधिक महत्व लोजपा (आर) को मिलेगा।

भाजपा की रणनीति अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की

भाजपा के रणनीतिकारों को भी नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली का बखूबी अंदाजा है। इसलिए पार्टी के रणनीतिकारों ने पहले ही इसे ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना ली है। बताया जा रहा है कि भाजपा इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में जेडीयू और भाजपा के बीच 122–121 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा हुआ था। जेडीयू को मिले 122 सीटों में से 115 पर नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को दिया था। वहीं भाजपा ने अपने कोटे की 121 सीटों में से 110 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 110 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा को 74 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जबकि भाजपा से ज्यादा यानी 115 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ 43 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए भाजपा की रणनीति अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तर्ज पर बेहतर रखने की है। भाजपा ने बिहार में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 के चुनाव में किया था। तब पार्टी ने अपने हिस्से की 102 सीटों में से 91 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

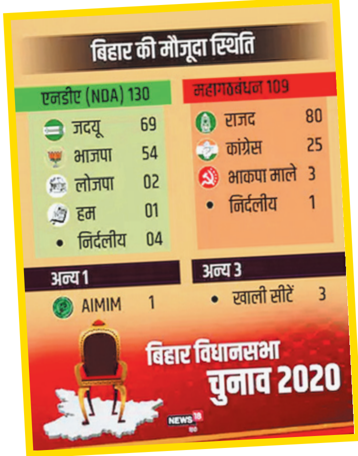

बिहार की मौजूदा स्थिति

एनडीए (NDA) 130		महागठबंधन 109	
जदयू	69	राजद	80
भाजपा	54	कांग्रेस	25
लोजपा	02	भाकपा माले	3
हम	01	निर्दलीय	1
निर्दलीय	04		
अन्य 1		**अन्य 3**	
AIMIM	1	खाली सीटें	3

बिहार विधानसभा चुनाव 2020

2025 का नया फॉर्मूला तैयार..

इस बार भाजपा ने बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव के 122–121 के फॉर्मूले को दरकिनार करते हुए 139–104 का नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले के हिसाब से 2020 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर लड़ने वाले नीतीश कुमार की पार्टी को इस बार सिर्फ 104 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। भाजपा इस फॉर्मूले के तहत 139 सीटें अपने कोटे में रखने की तैयारी कर रही है। भाजपा के आला नेताओं ने नीतीश कुमार को इस फॉर्मूले के बारे में बताते हुए यह भी साफ कर दिया है कि पार्टी अपने कोटे में से ही गठबंधन में शामिल अन्य दलों को सीटें देंगी। बताया जा रहा है कि 139 सीटों के अपने कोटे में से भाजपा 20 सीट चिराग पासवान की पार्टी को देगी और 7–7 सीट जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देगी। बाकी बची 105 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इस हिसाब से भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी से एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़कर बिहार एनडीए गठबंधन की राजनीति में न केवल बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी बल्कि इसके साथ ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवारों के चयन में भी अपना दखल बनाए रखेगी।

चिराग का बिहार में सीट बंटवारे पर खुलासा!

बिहार चुनाव पर बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि आप एक उदाहरण समझिए की एनडीए की स्थिति बिहार में क्या है। उन्होंने कहा कि हाल में उपचुनाव हुए थे। जहां एनडीए ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। उन सीटों को हासिल किया, जो कई टर्म से एनडीए के पास नहीं थे। जिसमें बेलागंज और तरारी प्रमुख सीट है। कुछ सीटें ऐसी भी थीं जहां एनडीए पहली बार जीता है। हमारे साथ विनिंग कॉम्बिनेशन है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। चिराग ने कहा कि मैं जितनी सीटें कल्पना करके रखी है, उतनी सीटें मुझे जरूर मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को एनडीए में सम्मान मिलेगा।उन्होंने कहा कि 2030 में वे खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन रोकने के लिए शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना होगा। बिहार के विकास और राजनीति पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिवाद तोड़कर विकास की राह पर आगे बढ़ने की जरूरत है। पासवान ने बताया कि वे बिहार में रिवर्स माइग्रेशन का सपना देखते हैं और इसके लिए शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर जोर दे रहे हैं।

आरोप-प्रत्यारोप का दिलचस्प दौर

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच आरोप–प्रत्यारोप का दिलचस्प दौर जारी है। नीतीश कुमार जहां एक बार फिर अपने पुराने रूप में आते हुए लालू यादव और राबड़ी देवी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। नीतीश तेजस्वी यादव पर निशाना साधने के साथ ही बिहार के मतदाताओं को 2005 से पहले के बिहार की भी लगातर याद दिला रहे हैं।लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की लड़ाई के बीच प्रशांत किशोर के एक बयान ने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। जन सुराज पार्टी के बैनर तले बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर ने यह बयान देकर सनसनी पैदा कर दी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे लेकिन नतीजों के बाद वे फिर से पाला बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर ने इसके साथ ही अपने कई पुराने बयानों को दोहराते हुए नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी कई तरह के गंभीर सवाल उठाए।

बोले पप्पू... मर जाएंगे लेकिन जात-पात नहीं करेंगे

उधर, इसी कार्यक्रम में शामिल हुए पप्पू यादव ने जाति और धर्म के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी को कोई वोट देना नहीं चाहता। इंडिया गठबंधन को लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन को बहुत समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव विकास पर नहीं बल्कि मार्केटिंग और पैसे पर होता है। नीतीश कुमार के गठबंधन में जाने की बात पर पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार इस समय न तो आरजेडी में सहज हैं और न ही बीजेपी में। उनका मानना है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस का गठबंधन बिहार में बड़ा बदलाव ला सकता है।पप्पू यादव ने कहा कि वे मर जाएंगे लेकिन चुनाव के लिए जात–पात नहीं करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताते हुए कहा कि सीएम का सपना देखना चाहिए, जनता तय करेगी। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अस्वस्थ जरूर हैं, लेकिन वह अभी भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हैं। बीजेपी अकेले चुनाव लड़कर देख ले तो पता चल जाएगा। INDIA गठबंधन कांग्रेस के बिना चुनाव लड़कर देख ले।

नीतीश के 'D' की काट के लिए तेजस्वी का YNR

आगामी विधान सभा चुनाव 2025 को ले कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का लेंथ और लाइन बिल्कुल क्लियर है। उनका मानना है कि वे किसी भी हाल में नीतीश कुमार को अब अपने साथ में नहीं लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति का सुर चाहे जो हो पर जिन नेताओं के आधार पर पार्टी का अब तक का हित सधते आया है, वे ही बयानों में आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े दिखते हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध राजनीति करते दिख रहे हैं। वहीं पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव या फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रही हैं। और यह सब तब हो रहा है जब तेजस्वी यादव. सत्ता तो सत्ता, विपक्ष के भी निशाने पर हैं। हालांकि तेजस्वी नीतीश के D यानी डेवलपमेंट के जवाब में अपना हथियार YNR को मान रहे हैं। तेजस्वी के YNR में Y का मतलब यूथ, N का मतलब नौकरी (सरकारी) और R का मतलब रोजगार–कारोबार। तेजस्वी यादव का कहना है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर 30 से 32 तक के नौजवान हैं, और वो युवा तेजस्वी को ही चुनेंगे। नौकरियों की बहार का दावा करने वाले तेजस्वी यादव यह कहते नहीं चूकते कि जब वे विपक्ष में थे और नौकरियां देने का दावा करते थे, तो नीतीश कहते थे कि पैसा बाप के घर से लाओगे कि जेल से। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी, मैंने चार लाख नौकरियों की पहल की। यही वजह भी है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के विरुद्ध पढ़ाई, कमाई और दवाई का नारा दिया।

झारखंड में राजनीतिक भूचाल के संकेत

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) में सीता सोरेन की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में बाहा पूजा में उनकी मौजूदगी ने इस अटकल को बल दिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद लगभग एक साल से सोरेन परिवार से उनकी दूरी थी। हालांकि, इस दौरान वह शिबू सोरेन से मिलती रही हैं लेकिन पारिवारिक कार्यक्रमों और नेमरा आने से परहेज करती रही हैं। यह घटनाक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सीता सोरेन पिछले कई महीनों से हेमंत सोरेन के किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने नेमरा नहीं आईं थीं। बीजेपी में शामिल होने के बाद से वह लगातार हेमंत सोरेन और जेएमएम पर हमलावर रही हैं। हालांकि, कुछ दिन पहले धनबाद में एक शादी समारोह में उन्होंने हेमंत सरकार की तारीफ की थी। पिछले कुछ महीनों में पहली बार सीता सोरेन, जेएमएम और हेमंत सोरेन के प्रति नरम रुख अपनाती दिखीं।

सीता सोरेन की घर वापसी की तैयारी!

सीता सोरेन की वापसी से संगठन को मिलेगी मजबूती

क्या सीता सोरेन वाकई जेएमएम में वापसी करेंगी? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। बीजेपी में उनका भविष्य क्या होगा? यह भी देखना होगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर सीता सोरेन जेएमएम में वापस आती हैं, तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। खासकर महिला वोट बैंक पर इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं, बीजेपी के लिए यह एक झटका होगा। आने वाले दिनों में सीता सोरेन के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। यह फैसला झारखंड की राजनीति की दिशा तय कर सकता है।

राजनीतिक मतभेद भुलाकर एकजुट होने की इच्छा

सीता सोरेन के राजनीतिक रुख में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें बीजेपी में अपेक्षित सफलता न मिली हो या फिर वह अपने परिवार के साथ राजनीतिक मतभेद भुलाकर फिर से एकजुट होना चाहती हों। यह भी संभव है कि वह राज्य की राजनीति में जेएमएम के साथ मिलकर अधिक सक्रिय भूमिका निभाना चाहती हों। जो भी हो, सीता सोरेन का अगला कदम झारखंड की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।

सीएम हेमंत की चचेरी बहन ने भी वापसी के दिए संकेत

15 मार्च को नेमरा में बाहा पूजा में शामिल होने के बाद, जेएमएम में उनकी वापसी की चर्चा तेज हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन और जिला परिषद सदस्य रेखा सोरेन ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन की परिवार से दूरी अब खत्म हो गई है। रेखा सोरेन ने यह भी कहा कि सीता जल्द ही बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल होंगी और पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम करेंगी। यह बयान सीता सोरेन के भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर कई सवाल खड़े करता है।

हेमंत-कल्पना के साथ दूरियां, सास रूपी सोरेन के साथ तस्वीरें

नेमरा गांव में आयोजित बाहा पर्व के मौके पर सीता सोरेन अपनी बेटियों के साथ पहुंचीं थीं। जहां सास रूपी सोरेन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सीता सोरेन की तस्वीरें आईं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन के साथ दूरियां साफ नजर आईं।

दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज

बीजेपी की नजर ट्रिपल इंजन सरकार पर, सियासी स्थिति भी पक्ष में

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। असेंबली चुनाव में 'आप 'को मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी एक और मोर्चे पर उसे झटका देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव अप्रैल में होने हैं। अभी मेयर का पद आम आदमी पार्टी के पास है। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी की नजर इस सीट पर है और उसके पास जीत की प्रबल संभावना है। दिसंबर 2022 में 'आप ' ने एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के राज को खत्म किया था। फरवरी 2023 में शैली ओबरॉय 'आप' की पहली मेयर बनीं। नवंबर 2024 में महेश खींची दूसरे मेयर चुने गए। अब बीजेपी वापसी की कोशिश में है।

दिल्ली नगर निगम की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो संख्या बल बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 131 वोट हैं, जबकि बहुमत के लिए 132-133 वोट चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के पास 122 वोट हैं। अगर मेयर चुनाव में 'आप' पकड़ बनाए रखना चाहती है तो उसे कांग्रेस और एक निर्दलीय पार्षद के समर्थन की जरुरत होगी। ऐसा होने पर ही 'आप' बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है।

क्या इस बार बीजेपी करेगी खेला?

बीजेपी को उम्मीद है कि वो एमसीडी में फिर से वापसी करेगी। 'आप' के लिए ये चुनाव अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद किंगमेकर की भूमिका में होंगे। उनका समर्थन जिस पार्टी को मिलेगा, उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। दिल्ली की जनता की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हैं। देखना होगा कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में जाती है।

2022 से मेयर पद पर है 'आप' का कब्जा

2022 के एमसीडी चुनाव के बाद 'आप' के 134, बीजेपी के 104, कांग्रेस के 9 और 3 निर्दलीय पार्षद थे। इस बदलाव की वजह खाली हुई सीटें हैं। इन सीटों पर चुनाव होने तक मौजूदा पार्षद ही वोट करेंगे। इसलिए बीजेपी के पास मेयर चुनाव जीतने का अच्छा मौका है। देखना होगा कि क्या 'आप' अपनी कुर्सी बचा पाती है या बीजेपी दिल्ली में अपना ट्रिपल इंजन सरकार बनाने में सफल रहेगी। दिल्ली की राजनीति के लिए ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा।

मेयर चुनाव पर सभी की निगाहें

एमसीडी में कुल 250 वार्ड हैं। इनमें से 12 खाली हैं। बीजेपी के 7 और आम आदमी पार्टी के 4 पार्षद विधायक चुने गए हैं। एक और पार्षद बीजेपी की कमलजीत सहरावत जून में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गईं। ऐसे में खाली सीटों पर चुनाव मेयर इलेक्शन के बाद होंगे। इसलिए अभी पार्षदों की संख्या 238 है। अध्यक्ष की ओर से मनोनीत 14 विधायकों को भी वोटिंग का अधिकार होगा। 10 सांसद (लोकसभा के 7 और राज्यसभा के 3) भी मेयर चुनाव में हिस्सा लेंगे।

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार

अमित शाह का एमपी दौरा अहम... मची हलचल, तय होगा प्रदेशाध्यक्ष?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मध्यप्रदेश के दौरे पर आने वाले है। इस बात की चर्चाएं तब से शुरू हो गई हैं जब से सीएम मोहन दिल्ली में शाह से मुलाकात कर लौटे है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अमित शाह अप्रैल के महीने में एमपी के दौरे पर आ सकते है। हालांकि अमित शाह का दौरा सरकारी माना जा रह है। शाह एमपी में किसानों को दूध पर बोनस देने की योजना का शुभारंभ करने भोपाल आ सकते है।

शाह का दौरा सरकारी तौर के अलावा राजनीतिक मायने भी रखा हुआ माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश में इन दिनों नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल तेज है और संभवता अप्रैल में नए अध्यक्ष का ऐलान भी होना है। शाह के दौरे के दौरान नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा की जा सकती है। शाह पहले भी एमपी के सीनियर नेताओं से चर्चा कर चुके है। शाह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन पर भोपाल आए थे। इस दौरान दिल्ली लौटते समय स्टेट हैंगर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को फोन करके बुलाया था और उन्से गुप्त चर्चा की थी। ऐसे में शाह का आने वाला एमपी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष का फैसला तो दिल्ली आलाकमान से होना है, लेकिन दावेदारों में हलचल तेज हो गई है। कई दावेदार तो भोपाल से दिल्ली की दौड़ लगाने लगे है। आपको यह भी बता दें कि अप्रैल में नए अध्यक्ष के ऐलान की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही है। प्रदेश के कई सीनियर नेता अध्यक्ष की दौर में शामिल होना बताए जा रहे है।

दिन में लड़ते... रात में गलबहियां डाले आए नजर....

मौजूदा राजनीति के दौर में जब नेता एक दूसरे को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के स्थान पर दुश्मन की तरह देखते हैं, ऐसे में प्रदेश की राजधानी भोपाल में लंबे समय बाद राजनीतिक सौहार्द देखने को मिला। यह अवसर उपलब्ध कराया विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने। पहले स्पीकर तोमर के सामने दिन में विधानसभा के अंदर परिवहन घोटाले को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ हमलावर थे। घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग पर सरकार सहमत नहीं हुई तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने पहले गर्भग्रह में जाकर हंगामा किया, नारेबाजी की। इसके बाद वाकआउट कर विधानसभा परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया। एक विधायक कुंभकर्ण बन कर आए थे। कांग्रेस विधायक बीन बजाकर उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश की सरकार कुंभकर्ण की तरह गहरी निद्रा में सोई हुई है। दूसरी तरफ विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद नजारा बिल्कुल अलग था। सभी मंत्री और विधायक तोमर के आमंत्रण पर विधानसभा के मानसरोवर सभागार पहुंचे। यहां फाग उत्सव का आयोजन था। खास बात यह थी कि यहां संगीत की धुन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के साथ हाथ पकड़ कर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार नाच रहे थे। कॉश, ऐसा राजनीतिक सौहार्द हमेशा बरकरार रहे।

मध्यप्रदेश कांग्रेस... अब नए चेहरों पर लगाएगी दाव

मध्यप्रदेश कांग्रेस इन दिनों अपने बुरे दौर से गुजर रही है। हालांकि पार्टी अपने आप को फिर से खड़ा करने का भरपूर प्रयास भी कर रही है। दरअसल, प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है। पार्टी अब मैदानी नेताओं से लेकर संगठन कार्यालयों में जमे नेताओं को बदलने की तैयारी में है। कांग्रेस ने पहले अपना प्रदेशाध्यक्ष बदला, नेता प्रतिपक्ष बदला, प्रदेश संगठन में कई पदों के चेहरे बदले, इसके बाद प्रदेश प्रभारी में बदलाव हुआ और अब पार्टी प्रदेश से लेकर जिला, ब्लॉक और गांव तक नई लीडरशिप को मौका देने का मन बना चुकी है। हालांकि पुराने चेहरों को दरकिनार नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसे चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है तो लंबे वक्त से सुस्त अवस्था में पदों पर जमे हुए है।प्रदेश स्तर के लीडरशिप की बात करें तो नेताओं में आपसी खींचतान के चलते पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस अब बड़े लेवल पर मंथन कर पार्टी में बदलाव की बयार लेकर आने में मूड में है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कांग्रेस सबसे पहले निचले स्तर से बदलाव की शुरूआत करेगी। पार्टी ग्राउंड लेवल से आगे बढ़ेगे और उच्च स्तर पर बदलाव करेगी। नीचले स्तर पर बदलाव से नेता दखल देने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे और धीरे धीरे पार्टी उच्च स्तर पर बदलाव करती पहुंचेगी। पार्टी का मुख्य फोकस जिला लेवल को मजबूत बनाने पर है। कुल मिलाकर पार्टी नीचे से लेकर उपर तक बदलाव करने की रणनीति पर काम कर रही है।

अकल चबूतरे से

जात-पात पे लात का राजनीतिक नवाचार

व्यंग्य **दिनेश विजयवर्गीय**

मुंशी आज एक सप्ताह बाद मॉर्निंग वॉक में मिला। मुझे पार्क की बैंच पर बैठा हुआ देख, लातें उछालता मेरी ओर बढ़ने लगा। उसके इस आचरण से मैं भी सकते में आ गया। आखिर सहज भाव से जीवन जीने वाले मुंशी को यह क्या खुराफात सूझी? जब मेरे पास आया तो मैंने पूछ ही लिया 'मुंशी! आज यह नया क्या कुछ कर रहे हो? आज तुम जैसे मॉर्निंग वॉक और योग करने वाले को यह क्या सूझी कि लातें उछाल रहे हो?

क्या किसी पर लातें बरसाने का अभ्यास कर रहे हो?'वह हंसता हुआ बोला, 'अंकल! जिस जात-पात पर देश का लोकतंत्र टिका है, उसी पर कोई प्रहार करे तो अजब-सा लगेगा ही। देखिए, राजनीति में जनता का मत प्राप्त करने के लिए अन्य विशेषताओं के साथ जात-पात के आधार पर टिकट वितरण करने का भी ध्यान रखा जाता है। भले पार्टी कहती रहे न जात पर न पात पर! पर सच तो यह है कि वह भी जात गंगा में डुबकी लगा तर जाने की संभावना बनाये रखते हैं। हमारे यहां तो आरक्षण का आधार ही जात-पात है। पर इन सबके चलते भी कोई वरिष्ठ नेता यह कहने लगे, जो करेगा जात की बात, उसको कसकर मारूंगा लात। तो फिर समझ लीजिए उनका चिंतन। लगता है वे लोकतंत्र को जात-पात से दूर रखकर उसे ऊपर उठाना चाहते हैं। सच्चे जन सेवक बन जन-मन में अपनी छवि सुंदरतम् बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं भी लात उठाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, पता नहीं कब, कहां काम आ जाए? आखिर लात मार कर ही तो कई शाकाहारी जीव मांसाहारी हिंसक जीवों से अपने जीवन की सुरक्षा करने का प्रयास करते हैं। यही सब सोच मैं भी अब इसकी प्रैक्टिस में तल्लीन हूं। इससे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कई लाभ हैं। पैरों में कभी सुन्नता नहीं आएगी और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर बना रहेगा। मैं धन्यवाद देता हूं नेताजी को जिन्होंने जात-पात की बात करने वालों को हाशिए में धकेलने जैसी बात कह दी। कुछ समय पहले अंकल आपको याद होगा कि एक मंत्री जी ने भी कहा था कि 'जो पैर छूएगा उसके काम की सुनाई नहीं होगी। सभी अपने-अपने नवाचार कर अपनी अलग पहचान बनाने में लग रहे हैं।'वाह भाई मुंशी! तुमने तो अपने समाचारों में से बड़ी मजेदार लोकतंत्रीय स्वस्थ परंपरा बनाए रखने वाली बातें सुना दीं।''अंकल! देखो लोकतंत्र को और अधिक बढ़िया और जनाकूल बनाने के लिए कब कौन-सा नेता क्या कुछ नवाचार कर बैठे, कुछ कह नहीं सकते, बस इंतजार करते रहिए।' इतना कह मुंशी एकदम उठा और घर की ओर चल दिया। उसके राजनीति में नवाचार की बात सुनकर, देर तक चिंतन करता रहा।

कही-सुनी

कीर्ति राणा

पानी के 200 करोड़ रुपए गए पानी में...

खंडवा नगर निगम को डेढ़ दशक पहले अमृत योजना के तहत 200 करोड़ रुपए मिले थे, जिससे शहर की पानी व्यवस्था को सुधारना था।यह जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी उसे योजना के अनुसार, पूरे शहर में जीआई पाइप लगाने थे, जिससे बिना मोटर के भी ऊपरी मंजिल तक पानी पहुंच सके, लेकिन टेंडर लेने वाली कंपनी ने जीआई पाइप की जगह घटिया प्लास्टिक पाइप लगा दिए गए, जिससे पाइपलाइन बार-बार फूट रही है और पानी की आपूर्ति ठप हो रही है। नगर निगम ने दावा किया था कि तीसरी मंजिल तक पानी बिना मोटर के पहुंचेगा, लेकिन हकीकत यह है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं साथ ही गंदे पानी की सप्लाई से डायरिया और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

कलेक्टर ने पकड़ा धान घोटाला

जबलपुर में 30 करोड़ रुपए के धान घोटाले का कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पर्दाफाश किया है। सहकारी समितियों के द्वारा जो धान बाहर जिलों के राइस मिलर को बेचा जाना बताया गया था उसे रुट पर पड़ने वाले टोल नाकों से परिवहन करने वाले वाहन गुजरे ही नहीं। ना तो राइस मिलर और ना ही सहकारी समितियां के लोग संबंधित वाहनों की जानकारी दे पाए। यह भी पाया गया कि जिन वाहनों से धान का परिवहन होना बताया गया उनमें आधा सैकड़ा से ज्यादा कारें शामिल थी।

कवि भी हो गए गोपी

भाजपा के वरिष्ठ नेता-पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा हर सप्ताह वॉट्सएप पर किसी आध्यात्मिक विषय पर तो अपने विचार साझा करते ही हैं, अब वे अधिकृत रुप से कवि भी हो गए हैं। उनकी लिखी कविताओं को संकलित किया है अम्मार रिजवी ने। ये संकलन विमोचित तो हुआ था काफिला मुहब्बत द्वारा आयोजित जश्ने सत्तन में । उनकी अतुकांत कविताओं का यह पहला संग्रह 'स्मृति-विस्मृति' शहर के प्रमुख लोगों तक उनके मित्र पहुंचा रहे हैं।

डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा का विरोध !

ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ आंबेडकर की प्रतिमा लगाने के निर्णय के विरोध में बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कई अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों के लिए आक्रोश का विषय बन गया है। यह प्रतिमा अधिवक्ता विश्वजीत रतौनिया और अधिवक्ता धर्मेंद्र कुशवाह के प्रयासों से यह प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसे अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि वे देश के पहले कानून मंत्री भी थे। अधिवक्ताओं का एक बड़ा वर्ग हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इस प्रदर्शन के निर्णय की कड़ी निंदा कर रहा है और इसे संविधान विरोधी करार दे रहा है।

लेनदेन में अटकी स्टेडियम की जमीन

उषा राजे होल्कर स्टेडियम से भी बड़े एक स्टेडियम की कमी तो शहर में लंबे समय से महसूस की जा रही है। सुपर कॉरिडोर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के लिए 20 एकड़ जमीन भी है लेकिन मामला अटका हुआ है जमीन की कीमत को लेकर। विकास प्राधिकरण इस जमीन को 200 करोड़ में देना चाहता है।एमपीसीए अधिकतम 70 करोड़ देना चाहता है। बीच का रास्ता निकालने के प्रयास चल जरुर रहे है लेकिन आयडीए को भी पता है जमीन सस्ते में लेकर एमपीसीए खेल तो महंगे करेगा।

ये नीम तो मीठा है

रतलाम के रुपाखेड़ा गांव को नीम ने आदर्श गांव बना दिया है। इस गांव के हर घर के सामने एक नीम का पेड़ लगा है । जिसकी शुरुआत गांव के लोगों ने वर्ष 2001-02 में की थी । तब बारिश बेहद कम हुई और सूखे जैसे हालत बने, तो गांव के ग्रामीणों ने तय किया कि हर घर के आगे एक नीम का पौधा लगाएंगे । करीब 25 सालों में अब यह नीम के पौधे बड़े वृक्ष में तब्दील हो चुके हैं और पर्यावरण के मामले में रुपाखेड़ा आदर्श गांव बन चुका है ।

100 नहीं अब 112 नंबर

पुलिस की डायल-100 की जगह नई एफआरवी (फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल) को नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 से जोड़ा जा रहा है, इससे इमरजेंसी में अलग अलग नंबर याद नहीं रखना पड़ेगा, इसके साथ ही रिस्पांस टाइम 20-25 से घटकर 15-20 मिनट रहेगा,यूरोपीय देशों की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल की पहचान डायल-100 की जगह डायल-112 से होगी । प्रदेश के 55 जिलों के लिए 1200 नई एफआरवी का टेंडर जारी हो चुका है, इससे न सिर्फ पुराने वाहनों की जगह नए वाहन आएंगे, बल्कि एफआरवी की संख्या भी 200 बढ़ जाएगी।

आप को पता है गुप्ता कहां हैं ?

एमपी के एक बड़े अफसर फरार* हो गए हैं। उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद राज्य सरकार ने भी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। प्रदेश के अनूपपुर में यह कड़ी कार्रवाई की गई है। यहां के कृषि विभाग के उपसंचालक और किसान कल्याण विभाग के परियोजना संचालक नारायण दास गुप्ता यानि एनडी गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। उनपर करोड़ों के गबन का आरोप है। इस मामले में एनडी गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है और वे फरार चल रहे हैं ।

दम तोड़ती नदी का दर्द

विदिशा जिले से निकलकर यूपी के जालौन में यमुना से मिलनेवाली सिंध नदी ने दम तोड़ दिया है। 470 किमी लंबे इलाके में बहने वाली यह नदी कई जगह सूखकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड जिलों से होकर बहते हुए यूपी के जालौन जिले में यमुना नदी में मिलती है। सिंध नदी का सूख जाना लाखों लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया है।

चुंबक प्रेमी पत्थर !

खंडवा के ग्राम गड़बड़ी माल में चुंबक प्रेमी पत्थर चर्चा में हैं। गांव के गिरवर सिंह राजपूत अपने साथियों के साथ चुंबकीय पत्थर लेकर कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को उन्होंने पत्थरों पर चुंबक लगाकर दिखाया तो उन्होंने खनिज विभाग से पत्थरों की जांच कराने की बात कही।राजपूत जब अमावस्या पर ग्राम कुकढाल से लगे जंगल के बैकवाटर में स्नान करने गए थे। उस दौरान वजन में भारी और अजीब नजर आने वाले पत्थरों को साथ ले आए थे।

बीडीए में आईएएस सीईओ

केंद्र की प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे 2018 बैच के आईएएस अधिकारी श्यामवीर सिंह नरवरिया को भोपाल विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के दामाद हैं । मंत्री की बेटी फलित सिंह से उनका विवाह हुआ है। वे मूल रुप से भिंड जिले के गोरमी क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव के रहने वाले हैं। प्राधिकरण सीईओ पद पर सीधी भर्ती के आईएएस की फिलहाल यह पहली पोस्टिंग है, संभव है अन्य प्राधिकरणों में भी आइएएस ही सीईओ पदस्थ किये जाएं। वैसे प्राधिकरणों में संचालक मंडल की घोषणा भी एक साल से नहीं हो पाई है।

सामान भी साथ ले गईं

रायसेन जिले में औबेदुल्लागंज जनपद पंचायत की पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी युक्ति शर्मा विवादों में घिर गई हैं। उन पर आरोप है कि वह जनपद का सरकारी सामान ऑटो में भरकर अपने साथ ले गईं । इस मामले में जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया ने औबेदुल्लागंज थाने को पत्र भेजकर युक्ति शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दे दिए हैं।जनपद पंचायत कार्यालय ने 3 मार्च को युक्ति शर्मा को दूसरा पत्र लिखकर सरकारी सामान लौटाने को कहा तो उन्होंने केवल बेड को लेकर जवाब दिया कि 'यदि इसका बिल जनपद में है तो दिखाया जाए, कंप्यूटर और अन्य सामान के बारे में शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया।

'भारत' की शुरुआत हो गई उज्जैन से

इंडिया नहीं भारत लिखने की आवाज अभी देश में गूंज रही है लेकिन पाणिनि संस्कृत विवि की कार्य परिषद ने सर्वानुमति से विवि के दस्तावेजों में भारत लिखने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है।कुलगुरु प्रो विजय कुमार सीजी की अध्यक्षता में पारित हुए इस प्रस्ताव से यह प्रदेश का पहला विवि भी बन गया है जो आधिकारिक अभिलेखों में भारत शब्द का प्रयोग करेगा।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक विनोद खुजनेरी द्वारा अपना देश प्रिंटर्स से अनुबंध पर 204 शेखर एवेन्यू, सांघी कॉलोनी, इंदौर 452001 से मुद्रित तथा प्रकाशित।
संपादकः विनोद खुजनेरी। मोबाइलः 98270-10709। आरएनआई पंजीयन क्रमांक 13186/67